लखनऊ

शनिवार 14 फरवरी, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 175

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है,तुझमे छुपी पाचन अभी बाकी है,तेरे इरादों की परीक्षा अभी बाकी है ।

TODAY WEATHER

DAY 20° Hi | NIGHT 10° Low

संक्षेप

पिछले 10 सालों जजों के खिलाफ हुईं 8,360 शिकायतें, सरकार ने लोकसभा में दी जानकारी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद में बताया कि पिछले दस सालों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के ऑफिस को मौजूदा जजों के खिलाफ 8,360 शिकायतें मिली हैं। यह जानकारी शुक्रवार को लोकसभा में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद (MP) मथेश्वरन वी.एस। के एक सवाल के जवाब में दी गई। सांसद ने ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार या दूसरी गंभीर गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों की लिस्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट से मिले डेटा के मुताबिक कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया कि 2016-2025 के बीच 8,360 शिकायतें मिलीं। मथेश्वरन ने यह भी पूछा कि क्या इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई की गई। हालांकि, कानून मंत्रालय के जवाब में उस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया। इसने यह भी नहीं बताया कि शिकायतों पर की गई कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं था। एक और सवाल यह उठाया गया कि क्या केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार, यौन दुर्व्यवहार या दूसरी गंभीर अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का रिकॉर्ड या डेटाबेस बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी सिस्टम के बारे में पता है। जवाब में इतना कहा गया कि भारत के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इन-हाउस प्रोसीजर के हिसाब से जजों के खिलाफ शिकायतें लेने के काबिल हैं। जवाब में कहा गया कि हायर ज्यूडिशियरी के सदस्यों के खिलाफ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रिवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (CPGRAMS) या किसी और तरीके से मिली शिकायतें CJI या संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी जाती हैं।

दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडिया के प्रतिनिधियों से की पूछताछ, साजिश के पहलू की जांच शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे के बहुप्रतीक्षित और वर्तमान में अप्रकाशित संस्मरण के कथित तौर पर लीक होने के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस संबंध में विश्व प्रसिद्ध पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के प्रतिनिधियों से पूछताछ की है। जांच का मुख्य केंद्र यह है कि क्या पुस्तक के संवेदनशील अंशों को सार्वजनिक करने के लिए रक्षा मंत्रालय (MoD) से अनिवार्य मंजूरी को जानबूझकर दरकिनार किया गया था। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने इससे पहले लगभग 15 सवालों के जवाब मांगने के लिए प्रकाशक को नोटिस जारी किया था और बुधवार को गुरुग्राम स्थित संबंधित कार्यालय का दौरा भी किया था। सूत्रों के अनुसार, बृहस्पतिवार को कंपनी प्रतिनिधियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए और अन्य सवालों के जवाब देने के लिए समय मांगा। पुलिस ने कहा कि जवाबों का विश्लेषण किया जा रहा है और प्रबंधन तथा प्रकाशन प्रतिनिधियों से आगे की पूछताछ किए जाने की संभावना है।

80 साल बाद बदला भारत का 'पॉवर सिस्टम', पीएम मोदी ने नए PMO 'सेवा तीर्थ' का किया उद्घाटन

सेवा तीर्थ से पीएम मोदी का पहला फैसला, लखपति दीदी का टारगेट किया दोगुना

नई दिल्ली, एजेंसी। सेवा तीर्थ से पहला फैसला लखपति दीदी के टारगेट को लेकर लिया गया है। पीएम राहत (PM RAHAT) स्कीम, लखपति दीदियों का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ किया गया। इस फैसले के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को दोगुना करके 2 लाख करोड़ रुपये किया गया है। वहीं 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 शुरू किया गया।

PM RAHAT स्कीम: हर नागरिक के लिए जीवन रक्षक सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने PM RAHAT स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत, दुर्घटना के शिकार लोगों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे यह पक्का होगा कि तुरंत मेडिकल मदद न मिलने से किसी की जान न जाए।

लखपति दीदियों का टारगेट दोगुना करके 6 करोड़ किया गया

सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदियों का लैंडमार्क पार कर लिया है, जो ओरिजिनल मार्च 2027 टाइमलाइन से एक साल से भी ज्यादा पहले है।पीएम मोदी ने अब मार्च 2029 तक 6 करोड़ लखपति दीदियों का एक नया, बड़ा टारगेट रखा है, जिससे स्केल और एस्पिरेशन दोनों दोगुना हो गए हैं।

किसानों को बड़ा बूस्ट

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना करके ₹2 लाख करोड़ किया गया। भारत की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मज़बूत करने के मकसद से, पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के खर्च को 1 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 2 लाख करोड़ करने की मंजूरी दी है।

10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0

भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को पावर देने के लिए खासकर डीप टेक, शुरुआती स्टेज के आइडिया, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ब्रेकथ्रू टेक्नोलॉजी में, पीएम ने 10,000 करोड़ रुपये के कॉर्पस के साथ स्टार्टअप इंडिया FoF 2.0 को मंजूरी दी है।

मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता था

दशकों से कई मंत्रालय सेंट्रल विस्टा एरिया में पुराने और बिखरे हुए ऑफिस से काम करते थे, जिससे कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती थीं, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता था और काम करने की क्षमता कम होती थी। नए कॉम्प्लेक्स इन कामों को इंटीग्रेटेड, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं में एक साथ लाते हैं, जिसका मकसद कोऑर्डिनेशन और वर्कफ़्लो को बेहतर बनाना है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन दोनों में डिजिटली इंटीग्रेटेड ऑफिस, सेंट्रलाइज्ड रिसेप्शन सुविधाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास पब्लिक इंटरफ़ेस ज़ोन हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना करके ₹2 लाख करोड़ किया गया। भारत की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मज़बूत करने के मकसद से, पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के खर्च को 1 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 2 लाख करोड़ करने की मंजूरी दी है।

हर नागरिक के लिए जीवन रक्षक सुरक्षा

प्रधानमंत्री ने PM RAHAT स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल के तहत, दुर्घटना के शिकार लोगों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे यह पक्का होगा कि तुरंत मेडिकल मदद न मिलने से किसी की जान न जाए।

मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता था

दशकों से कई मंत्रालय सेंट्रल विस्टा एरिया में पुराने और बिखरे हुए ऑफिस से काम करते थे, जिससे कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती थीं, मेंटेनेंस का खर्च बढ़ता था और काम करने की क्षमता कम होती थी। नए कॉम्प्लेक्स इन कामों को इंटीग्रेटेड, भविष्य के लिए तैयार सुविधाओं में एक साथ लाते हैं, जिसका मकसद कोऑर्डिनेशन और वर्कफ़्लो को बेहतर बनाना है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन दोनों में डिजिटली इंटीग्रेटेड ऑफिस, सेंट्रलाइज्ड रिसेप्शन सुविधाएं और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए खास पब्लिक इंटरफ़ेस ज़ोन हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना करके ₹2 लाख करोड़ किया गया। भारत की पूरी एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मज़बूत करने के मकसद से, पीएम मोदी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के खर्च को 1 लाख करोड़ रुपये से दोगुना करके 2 लाख करोड़ करने की मंजूरी दी है।

'सत्ता के लिए बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही कांग्रेस'

नई दिल्ली, एजेंसी। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी बिन पानी मछली की तरह तड़प रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 60 साल तक देश की सत्ता में रही, आज उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि देखिए, दो-तीन उदाहरण हैं। जब सदन चला तो राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस नेताओं ने हंगामा किया और कोई आधार नहीं था। इनकी स्थिति ऐसी थी कि 'आसमान से गिरे, खजूर पर अटके'। भाजपा सांसद ने कहा कि नेता विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करने दी और जब बजट शुरू हुआ, तो बजट पर कुछ नहीं बोले, बाकी सब कुछ बोले। जिस व्यक्ति को ट्रेड एंड कॉमर्स और फाइनेंस में अंतर नहीं पता, वो बाकी क्या करेगा? जिसको यह नहीं पता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर क्या बोले और बाकी पर क्या बोले, तो आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है। टेबल पर कूदकर हंगामा करते हैं, बेवजह के आरोप लगाते हैं, उनकी बातों में तथ्य होते नहीं हैं। स्पीकर का घेराव करते हैं। यह कैसी हालत है? कांग्रेस पार्टी यह करती है। 60 साल तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, जो आज सत्ता से बाहर है, उसकी स्थिति यह है कि सत्ता के लिए ऐसे तड़प रही है जैसे पानी बिन मछली तड़पती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 95 चुनाव हार चुकी है।

राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार, केंद्रीय मंत्री रीजीजू बोले-भाजपा सांसद ने दिया है नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की योजना छोड़ दी है क्योंकि भाजपा के एक सांसद ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता के खिलाफ एक 'विशिष्ट प्रस्ताव' शुरू करने के लिए नोटिस दिया है।

रीजीजू ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष से सलाह ली जाएगी कि इस मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए, आचार समिति को भेजा जाए या सीधे लोकसभा में लाया जाए। उन्होंने कहा, 'अभी यह तय नहीं हुआ है।' उन्होंने कहा कि चूंकि एक सदस्य ने निजी तौर पर प्रस्ताव के लिए पहले ही नोटिस दे दिया है, इसलिए सरकार अपना प्रस्ताव पेश करने से बचेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ "विशिष्ट प्रस्ताव" लाने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। दुबे के अनुसार, उन्होंने अपने नोटिस में कहा है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष विदेश जाते हैं और भारत विरोधी तत्वों के साथ सांठगांठ करते हैं। विशिष्ट प्रस्ताव स्वतंत्र होता है, जिसे सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और जिसे किसी फ़ैसले या राय को व्यक्त करने के लिए तैयार किया जाता है। दुबे ने कहा, "कोई विशेषाधिकार हनन नोटिस नहीं दिया है। मैंने एक विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है।'

यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, सब चंगा है... विधानसभा में बोले सीएम योगी

आर्यावर्त क्रांति

लखनऊ। यूपी विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा।उन्होंने कहा, पहले लोग यूपी को शक की निगाह से देखते थे। समाजवादी पार्टी की वजह से प्रदेश की छवि खराब हुई। चेहरे पर धूल थी और ये आईना साफ करते रहे। अब बिना भेदभाव के हर वर्ग को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब यूपी बीमारू नहीं तेज विकास वाला राज्य है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या-प्रयागराज में करोड़ों लोग आ रहे हैं। अब यूपी उपद्रव का नहीं उत्सव का प्रदेश है। अब यूपी गुंडा टैक्स, वसूली से मुक्त है। अब यूपी में ना कर्फ्यू है ना दंगा है, सब चंगा है।

यूएस ट्रेड डील पर होगा महासंग्राम? राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ किया मंथन

नई दिल्ली, एजेंसी। मजदूरों और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच आज उन्होंने संसद भवन में किसान यूनियनों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर अपना विरोध जताया। साथ ही मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की रोजी-रोटी को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई।

राहुल गांधी ने कहा कि ट्रेड डील ने खेती के इंपोर्ट के लिए रास्ता खोल दिया है। जल्द ही कई दूसरी फसलें भी इंपोर्ट होंगी। किसान नेताओं और राहुल गांधी ने इस डील का विरोध करने और किसानों और खेत मजदूरों की रोजी-रोटी की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर चर्चा की। इस चर्चा में सुखपाल एस खैरा, रंजीत संधू और अशोक बलहारा भी मौजूद रहे।

किसान-विरोधी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे

किसान नेताओं के साथ इस मीटिंग से पहले राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा।जो भी ट्रेड डील किसानों की रोज़ी-रोटी छीने या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है।अन्नदाताओं के हितों से किसान-विरोधी मोदी सरकार को समझौता नहीं करने देंगे।

गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले- देश में सिविल वॉर भड़काना चाहते हैं?

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन पर गलत सूचना फैलाने और देश में गृहयुद्ध भड़काने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा गांधी के आचरण पर लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता किसानों के मुद्दों और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के उन बयानों का हवाला दिया, जिनमें किसानों के हितों से समझौता न करने का आश्वासन दिया गया था।

रैली में भीड़ पर पाबंदी से भड़के एक्टर विजय, सीएम स्टालिन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली, एजेंसी। अपनी चुनावी सभा में मात्र 4,998 लोगों के शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद, तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) प्रमुख विजय ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राज्य द्वारा लागू किए गए मानक संचालन प्रक्रियाएं स्टालिन की कार्यप्रणाली हैं। सीलानाइकेनपत्ती में एक चुनावी रैली में सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने एमके स्टालिन सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) को राजनीतिक रैलियां आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर रही है, जबकि अन्य को अनुमति दे रही है। विजय ने कहा कि वह सलेम केवल वोट मांगने नहीं, बल्कि न्याय मांगने आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां अन्य पार्टियों को अनुरोध करने पर तुरंत अनुमति मिल जाती है, वहीं तमिलगा वेट्री कज़गम को अनुमति देने से इनकार कर दिया जाता है। विजय ने कहा कि वे अन्य पार्टियों को सम्मेलन, सार्वजनिक सभाएं या हॉल में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति देते हैं और जगह उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सिर्फ हमें, वे न तो जगह देते हैं और न ही देने की अनुमति देते हैं। अन्य पार्टियों के लिए, वे उपयुक्त स्थान और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि वे लोगों से मिल सकें या लोग उनसे मिल सकें। लेकिन मुझे, वे न तो यह सुविधा देते हैं और न ही देने की अनुमति देते हैं। यह कैसा न्याय है? उन्होंने आगे कहा कि वे एसओपी की बात करते हैं। इसका पूरा नाम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन मेरे लिए, इसका मतलब स्टालिन-ओह सॉरी, स्टालिन सर ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगता है। एहतियात के तौर पर, कार्यक्रम स्थल पर पार्टी सदस्यों और पदाधिकारियों के पहचान पत्रों का कड़ाई से सत्यापन किया गया।

'लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ', राज्यसभा में भाषण के बड़े हिस्से को हटाने पर भड़के खरगे

नई दिल्ली, एजेंसी। राज्यसभा में शुक्रवार (13 फरवरी) को बोलते हुए विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पिछले संबोधन के बड़े हिस्से को सदन के रिकॉर्ड से हटाने पर नाराजगी जताई। खरगे ने कहा कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी औचित्य के आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। खरगे ने इस कदम को 'लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ' बताया।

इसी के साथ उन्होंने कहा कि हटाए गए भाषण में सरकार की नीतियों की आलोचनाएं शामिल थीं, जिसे उन्होंने एक विपक्षी सदस्य के रूप में उजागर करना अपना कर्तव्य बताया। इसी के उन्होंने हटाए गए भाषण के हिस्सों को बहाल करने का भी आग्रह किया।

बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के हटाया भाषण का हिस्सा: खरगे

राज्यसभा में बोलते हुए खरगे ने कहा, '4 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। जब मैंने राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया वीडियो देखा, तो मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिना किसी उचित स्पष्टीकरण या औचित्य के हटा दिया गया है।' उन्होंने कहा कि समीक्षा करने पर मैंने पाया कि हटाए गए हिस्से में संसद में वर्तमान सरकार के कामकाज पर मेरी टिप्पणियां और तथ्यात्मक संदर्भ शामिल थे। मैंने प्रधानमंत्री की कुछ नीतियों की आलोचना भी की, जो विपक्ष के सदस्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, विशेषकर तब जब इन नीतियों का जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है।'

फिर बहाल करने की खरगे ने की मांग

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने पांच दशकों से अधिक समय तक सांसद के रूप में सेवा की है, एक विधायक और संसद सदस्य के रूप में समर्पण के साथ काम किया है, हमेशा गरिमा, शिष्टाचार और भाषा के प्रति सम्मान को बनाए रखा है। इसलिए, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि मेरे भाषण के जिन अंशों को हटाया गया है, उन्हें बहाल किया जाए, क्योंकि उनमें कोई असंसदीय या मानहानिकारक शब्द नहीं हैं, और न ही वे नियम 261 का उल्लंघन करते हैं। मेरे भाषण के इतने बड़े हिस्से को हटाना लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है।' जिस पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने खरगे के हटाए गए बयानों को बहाल करने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हटाए गए अंशों को बहाल नहीं किया जा सकता और इस बात पर जोर दिया कि इस मामले पर अध्यक्ष को निर्देश देना सही नहीं और लोकतांत्रिक नहीं है।

दिल्ली के तीन स्कूल को बम की धमकी, ईमेल मिलने पर तलाशी कर विद्यार्थियों को निकाला सुरक्षित बाहर

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के कम से कम तीन स्कूल को शुक्रवार सुबह बम की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए, जिसके बाद अधिकारियों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मध्य दिल्ली के झंडेवालान स्थित बीटी तमिल स्कूल ने सुबह करीब 9.12 बजे डीएफएस को धमकी मिलने की सूचना दी।

एक अन्य स्कूल ने अभिभावकों को भेजे संदेश में कहा, ₹प्रिय अभिभावकों, आज सुबह स्कूल को एक सुरक्षा संबंधी धमकी प्राप्त हुई। एहतियात के तौर पर आवश्यक सुरक्षा उपायों के लिए पुलिस स्कूल में मौजूद है। सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्कूल को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी।₹ अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

गाजियाबाद में बीजेपी नेता के घर पर लगी आग, धमाके से दहशत में लोग, घरवालों ने लगाए गंभीर आरोप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के भोपुरा स्थित डीएलएफ कॉलोनी के एक घर में भीषण आग लग गई। भाजपा नेता मान सिंह गोस्वामी के घर पर आग लगने से एक-एक कर धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज से लोग दहशत में आ गए। हादसे के समय मान सिंह का परिवार घर के अंदर मौजूद था, जिसने किसी तरह ऊपरी हिस्से से निकलकर पड़ोसी मकान के रास्ते नीचे उतरकर अपनी जान बचाई।

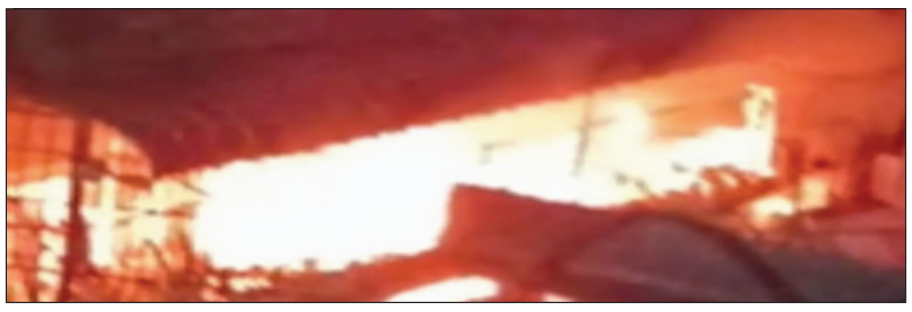

मान सिंह गोस्वामी भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं और स्थानीय पार्षद रेखा गोस्वामी के पति हैं। परिवार के लोगों ने बताया कि धमाकों के साथ घर के एक हिस्से में आग की लपटें उठने लगीं। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और घटना की सूचना पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी गई।

भाजपा नेता मानसिंह का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। यह आग कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी ने जानलेवा हमला किया है। घटना 10 / 11 फरवरी की देर रात की बताई जा रही है। मान सिंह ने बताया कि देर रात वह अपने घर में सो रहे थे, तभी उनके कानों में बहुत तेज धमाके की आवाज आई, लेकिन जब तक वह बिस्तर से उठकर बाहर पहुंचे, तब तक घर के मुख्य द्वार का हिस्सा आग और धुएं की लपटों से घिरा हुआ था।

एसीपी अतुल कुमार ने बताया कि घर के बाहर ही बिजली आदि का बोर्ड बना हुआ है, जिस पर एमसीबी आदि के स्विच लगे हुए हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि हमने जांच की तो वहां पर किसी प्रकार के हमले के कोई साक्ष्य नहीं मिले। हमने फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से भी जांच करवाई तो उन्होंने भी आशंका जताई है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है।

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, मान सिंह गोस्वामी के भाई की आसपास रहने वाले चार-पांच लोगों से बहस और हाथापाई कुछ दिन पहले हुई थी। लोगों का कहना है कि कहीं उन्हीं असामाजिक तत्वों ने मानसिंह गोस्वामी के घर के अंदर आग तो नहीं लगाई। भाजपा नेता मानसिंह चौहान ने पुलिस को एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर हमले होने की शिकायत की है। साथ यह भी कहा है कि हो ना हो यह किसी ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ योजना बनाकर उनकी हत्या करने की साजिश की है।

मकान के अंदर रखा सामान जलकर नष्ट

स्थानीय लोगों ने पहले खुद से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेज होने के कारण स्थिति गंभीर हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन संकरी गली और सड़क पर खड़े वाहनों के कारण उसे घर तक पहुंचने में कठिनाई हुई। बाद में आग पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया। घटना में मकान के अंदर रखा घरेलू सामान, फर्नीचर और अन्य कीमती वस्तुएं जलकर नष्ट हो गईं। फायर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगना प्रतीत हो रहा है। फिर भी परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

अमृत सरोवर या भ्रष्टाचार का तालाब

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले का सबसे भ्रष्ट ब्लॉक बनने की होड़ अगर कहीं दिखती है तो वह है दोस्तपुर। ब्लॉक दोस्तपुर की ग्राम पंचायत बनी में बना तथाकथित अमृत सरोवर आज खुद अपनी बदहाली पर आँसू बहा रहा है। अम्बेडकर पार्क के बगल में बना यह सरोवर गाँव की शान नहीं बल्कि सरकारी धन की खुली लूट का स्मारक बन चुका है। मुख्यमंत्री का सपना था कि हर गाँव में अमृत सरोवर बने। जल संरक्षण हो, सौंदर्यीकरण हो, ग्रामीणों को बैठने की व्यवस्था हो, स्वच्छता हो। लेकिन बनी ग्राम सभा में हालात यह हैं कि न बैरिकेडिंग, न बेंच, न इंटरलॉकिंग, न साफ-सफाई। हालत इतनी बदतर कि गाँव के बीच के पुराने गड्ढे से भी ज्यादा जर्जर दिखाई देता है यह अमृत सरोवर। सवाल उठता है आखिर लाखों रुपये गए कहाँ। जब सचिव के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले सुषमा के भाई धर्मेन्द्र से फोन पर बात की गई तो उनका जवाब बेहद सीधा और बेशर्मी से भरा था जितना पैसा निकला है उतना काम हुआ है। यानी कागजों में सब चकाचक, ज़मीन पर सब ध्वस्त। वहीं जब खंड विकास अधिकारी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पत्रकार को ब्लॉक बुलाने की सलाह दे दी आ जाइए फाइनल चेक कर बताते हैं। गलती हुई तो खुद एफआईआर कराएंगे। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार की तस्वीरें देखने के लिए भी अब पत्रकार को ब्लॉक में हाज़िरी लगानी पड़ेगी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी सिर्फ फाइलों तक सीमित है।

पांच दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम पूरा कर वापस लौटने पर हुआ भव्य स्वागत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज, सुल्तानपुर के 40 विद्यार्थियों का दल, जो उत्तराखंड में आयोजित पांच दिवसीय शैक्षणिक एक्सपोजर विजिट पर गया था, आज सकुशल विद्यालय लौट आया। विद्यार्थियों के आगमन पर विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा वातावरण देखने को मिला। छात्रों का स्वागत जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रकाश सिंह, उप जिलाधिकारी करम सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक जटाशंकर यादव, विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मनोज कुमार तिवारी एवं समस्त शिक्षकगण द्वारा बड़ी गर्मजोशी और आत्मीयता के साथ किया गया।

उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी को इस शैक्षणिक दल को जिले के प्रतिष्ठित राजनीतिक एवं समाजसेवी, विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। विद्यार्थियों ने उत्तराखंड स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून; भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की तथा पतंजलि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। यह यात्रा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की छात्र-केंद्रित एवं दूरदर्शी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक ज्ञान के साथ-साथ अन्य राज्यों की संस्कृति, इतिहास, भाषा, वैज्ञानिक उपलब्धियों और शैक्षणिक वातावरण से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना था। पांच दिनों तक चले इस भ्रमण में छात्रों ने विभिन्न प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों एवं शैक्षणिक परिसरों का अवलोकन किया तथा विशेषज्ञों से संवाद कर नई जानकारियां प्राप्त कीं। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक सूर्य प्रकाश सिंह जी ने कहा कि अनुभवात्मक शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का आधार है। उप जिलाधिकारी करम सिंह ने छात्रों के अनुशासन और जिज्ञासा की सराहना की। प्रधानाचार्य डॉ. मनोज कुमार तिवारी ने मार्गदर्शी शिक्षकों पंकज कुमार एवं जयप्रकाश यादव के सफल नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह यात्रा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगी। कार्यक्रम का समापन विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ हुआ। विद्यालय परिवार ने इस शैक्षणिक भ्रमण को शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक और सराहनीय पहल बताया।

लुटेरी दुल्हन गैंग का पुलिस ने किया भण्डाफोड़

सुल्तानपुर। कभी नीले ड्रम को चर्चा में लाने वाली मुस्कान की हरकतों ने विवाहिता जीवन जी रहे पतियों के चेहरे पर खौफ पैदा कर दिया था और देश में मुस्कान के कारनामों की चर्चा हो रही थी तो इसी बीच एसपी चारु निगम ने सुल्तानपुर का चार्ज लेते की एक सप्ताह के भीतर एक नई मुस्कान के गैंग का पर्दाफाश कर फिर से मुस्कान नाम को चर्चा में ला दिया है। दरअसल चारू निगम की टीम ने धनपतगंज थाने में दर्ज एक मामले में मुस्कान जोकि पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन सुमन का उपनाम है उसके गैंग के अन्य सदस्यों को पकड़ा है। इस बार की मुस्कान नीले ड्रम की वजह से नहीं बल्कि लाल जोड़ो के वेशभूषा के लिए जानी जाएगी जो कि दुल्हन बनाकर युवकों को लूटने का काम करती थी। बकायदे मंदिर में शादी करती और प्लान के मुताबिक अपने गैंग की महिला और पुरुष सदस्यों को साथ लाकर बीच रास्ते में दूल्हे और उसके परिवार को लूटने का काम करती थी।

'खिलौने से मत डराओ...' सुनकर भड़के दामाद ने सास को मार दी सच में गोली, मौके पर ही मौत

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। मुरादाबाद में दामाद ने मामूली कहासुनी के दौरान सास को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद कातिल दामाद तमंचा लहराते हुए अपने साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है।घटना मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके की है, जहां देर रात कटघर थाना क्षेत्र के पंडित नगला निवासी गुलनवाज़ अपनी ससुराल पहुंचा। वहां उसकी अपनी सास से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद ने महिला रुखसाना की जान ले ली।

आरोपी युवक गुलनवाज़ की शादी मृतका रुखसाना की बेटी साहिबा से 4 वर्ष पहले हुई थी और युवक का अपने ससुरालियों से विवाद चल रहा था। विवाद के चलते रुखसाना की बेटी साहिबा मायके में रह रही थी। गुलनवाज़ रात लगभग 7 बजे अपने साथी मुस्तफा के साथ अपनी ससुराल पहुंचा। वहां उसकी सास किचन में खाना बना रही थी। गुलनवाज़ नशे का आदी बताया जा रहा है और पैसों को लेकर आए दिन विवाद रहता था।

बताया गया कि किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और इसी के बाद गुस्से में आकर युवक ने अवैध तमंचे से सास की गर्दन के समीप गोली मार दी, जिससे महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी और घर में कोहराम मच गया। घटना को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। आनन-फानन में परिजन रुखसाना को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

क्या बोली बोटी?

मृतका की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका बहनोई नशे का आदी था और वह आज अपने एक दोस्त के साथ उनके घर आया था। उसकी मां उसे किसी बात को लेकर समझाने की कोशिश कर रही थी। इसी बात पर उसके बहनोई को इतना गुस्सा आया कि उसने तमंचे से उसकी मां को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतका की बेटी के मुताबिक, जब उसकी मां पर तमंचा निकाला गया तो उसने कहा, इस खिलौने से मुझे मत डराओ, इसे जेब में रखो। इसके तुरंत बाद आरोपी ने उसकी मां को गोली मार दी।

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गुलनवाज़ का ससुरालियों से विवाद चल रहा था। रात करीब 7 बजे उसने अपनी सास को गोली मार दी। इलाज के दौरान रुखसाना की मौत हो गई। मृतका की बेटी साहिबा ने अपने पति गुलनवाज़ और उसके साथी मुस्तफा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने घटना में शामिल मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी गुलनवाज़ की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है।

काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर हाथ जोड़कर खड़ी रहेगी यूपी पुलिस, क्यों लिया गया ये फैसला?

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि पर पुलिस एक अलग अंदाज में नजर आएगी। महाशिवरात्रि पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत पुलिसकर्मी हाथ जोड़कर करेंगे। मंदिर के एंट्री पॉइंट पर पहुंचे ही वहां मौजूद पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं का वेलकम हाथ जोड़कर करेंगे। इसके लिए पुलिसकर्मियों को श्रद्धालुओं से व्यवहार की सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी गई है।

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि वर्दी सेवा, सहयोग एवं विश्वास का प्रतीक है और प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं आत्मीय अनुभव प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महाशिवरात्रि पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सुरक्षा कर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी गई है।

मंदिर में ऐसे प्रवेश कराएंगे पुलिसकर्मी

घंटों लाइन में लग कर जब श्रद्धालु मंदिर परिसर में पहुंचे तो सुरक्षा कर्मी उनको प्रणाम की मुद्रा में अंदर प्रवेश कराएंगे और उनको सर /मैडम कह कर संबोधित करेंगे। कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि 'देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु लंबी यात्रा एवं प्रतीक्षा के कारण धैर्य खो सकते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों को प्रत्येक परिस्थिति में संयमित, विनम्र एवं सकारात्मक व्यवहार बनाए रखते हुए धैर्यपूर्वक उनकी काउंसलिंग करनी होगी।

सीसीटीवी कैमरे से होगी पुलिसकर्मियों की निगरानी

पुलिस कमिश्ननर निर्देश दिया गया है कि श्रद्धालुओं द्वारा पूछे जाने पर वाराणसी की प्रमुख व्यवस्थाओं, मार्गदर्शन, सुरक्षा प्रबंधों एवं महत्वपूर्ण स्थलों के संबंध में शालीनता एवं स्पष्टता के साथ आवश्यक जानकारी प्रदान करें। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मंदिर परिसर में तैनात पुलिस कर्मियों के व्यवहार की सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कंट्रोल रूम में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाएगी।

अनुचित आचरण पर पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

किसी भी प्रकार की अभद्रता और अनुचित आचरण पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजन एवं दूरदराज से आए श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने, आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने और प्राथमिकता के आधार पर मार्गदर्शन देने के निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए हैं।

तहसील सदर जहां अधिकारियों के आदेश का होता है सौदा

सुल्तानपुर। खण्ड शिक्षा अधिकारी कुड़वार रोजी सिंह ने जूनियर हाईस्कूल भण्डरा की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाए जाने के लिए उपजिलाधिकारी सदर से राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन कराए जाने के लिए दिनांक 12/11/25 को किए गए पत्राचार पर उपजिलाधिकारी सदर विपिन द्विवेदी द्वारा तहसीलदार सदर सुल्तानपुर को कार्रवाई करने हेतु आदेश जारी किया गया था जिस पर तहसीलदार सदर देवानंद तिवारी ने नायब तहसीलदार कुड़वार धर्मेंद्र यादव और राजस्व निरीक्षक कुड़वार शिव प्रसाद कनौजिया को अपने पत्रांक संख्या 7606 दिनांक 19/11/25 को कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश जारी किया। जिस पर नायब तहसीलदार कुड़वार धर्मेंद्र यादव द्वारा जांच भी कराई गई, जांच में जुनियर हाई स्कूल की जमीन पर अवैध निर्माण पाया भी गया है यही से नायब तहसीलदार कुड़वार धर्मेंद्र यादव द्वारा मामले में सौदे बाजी का खेल शुरू हो गया।

मनरेगा बचाओ संग्राम : सड़कों पर कांग्रेसियों का हुजूम, सरकार पर बरसे कांग्रेसी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आवाहन एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने "मनरेगा बचाओ संग्राम" के तहत जोरदार पदयात्रा निकाली। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा व ब्लॉक अध्यक्ष रामभवन पांडेय के नेतृत्व में सदर विधानसभा (जयसिंहपुर) क्षेत्र में निकली इस पदयात्रा में कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिकों और महिलाओं की भागीदारी रही। पदयात्रा का शुभारंभ जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बगिया चौराहे से हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जॉब कार्ड धारकों ने हाथों में मनरेगा बचाओ संग्राम का बैनर महात्मा गांधी की फ़ोटो और कांग्रेस का झंडा लेकर मनरेगा के समर्थन में नारेबाजी की। बगिया चौराहे से शुरू हुई यात्रा सदरपुर जयसिंहपुर गाँव कान्हापुर सुकुलबिजौली होते हुए जयसिंहपुर तहसील मुख्यालय पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा के साथ पदयात्रा का समापन हुआ। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव एवं पश्चिम बंगाल स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य बीपी सिंह भी कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। जनपद की विधानसभा कादीपुर सुल्तानपुर व सदर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसियों ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन ने भाग लिया। जगह-जगह ग्रामीणों ने यात्रा का स्वागत किया और मनरेगा योजना को कमजोर किए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद की। सुल्तानपुर 188 विधानसभा की पदयात्रा जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा व शहर अध्यक्ष शकील अंसारी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से सुपर मार्केट डाकखाना चौराहा गन्दानाला अस्पताल चौराहा रोडवेज बस स्टेशन से विकास भवन के सामने से होते हुए पंत स्टेडियम होकर लाल डिग्गी चौराहे तक निकाली गई, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा जैसी जनहितकारी योजना को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के हक पर डाका डाल रही है। मजदूरों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा, बजट में कटौती की जा रही है और काम के अवसर घटाए जा रहे हैं। कांग्रेस यह अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मनरेगा के साथ छेड़छाड़ बंद नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को और तेज करेगी।

टीबी एवं कैंसर की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लगाया कैंप

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में जनपद में कल 100 कैंप टीबी एवं कैंसर का आयोजित किया जाना था, जिसके क्रम में आज डॉ. भारत भूषण के निर्देशन में रायबरेली रोड अमहट पुलिस चौकी के पास काशीराम कॉलोनी में एक कैंप का आयोजन किया गया। जिसमें जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. आरके कनौजिया, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय गुप्ता, एनसीडी क्लीनिक के चिकित्सा अधिकारी डॉ. इमरान युसूफ, डॉ.पवन कुमार गुप्ता की मौजूदगी में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में टीबी की जांच स्तन, गर्भाशय ग्रीवा, मुख कैंसर की जांच, शुगर की जांच, हाइपरटेंशन की जांच आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ आभा आईडी भी बनाया गया। जिसमें कुल 73 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग किया गया, केंद्र सरकार से प्राप्त हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीन से डीआरए नाज़नीन के द्वारा सभी 73 व्यक्तियों का सीने का एक्सरे किया गया, जिसमें कुल 6 लोगों में टीबी के लक्षण पाए गए। जिनका बलगम का सैंपल लेकर जांच किया गया तथा शुगर के साथ लोग हाइपरटेंशन के 11 लोगों पाए गए। कैंप में मुख्य रूप से टीबी क्लीनिक के वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक सुरेश कुमार, अर्बन कोऑर्डिनेटर विकास यादव, रणवीर यादव एलटी, विकास पाण्डेय एल टी, ममता तिवारी एएनएम, शहनाज बानो, आंगनवाड़ी अंजली गुप्ता, आशा ममता, एवं दीपा श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहकर कैंप में उपस्थित रहे।

यूपी में महंगी होगी शराब, एक बोतल पर कितना ज्यादा देना होगा पैसा?

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। सरकार ने शराब उद्योग को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बुधवार को कैबिनेट ने नई आबकारी नीति और आबकारी निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत घरेलू बाजार में देशी शराब के दाम बढ़ेंगे, जबकि विदेशी बाजार में यूपी की शराब को बढ़ावा देने की तैयारी की गई है। इस नीति से राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि की उम्मीद है, साथ ही किसानों और उद्योग को फायदा पहुंचेगा।

नई नीति के अनुसार 1 अप्रैल से 36 प्रतिशत अल्कोहल वाली देशी शराब की ड्यूटी 165 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 173 रुपये कर दी गई है। इससे बोतल के दाम में औसतन 5 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, अन्य श्रेणियों की शराब के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

विदेशी शराब की फुटकर दुकानों के राजस्व में 7.5 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। आबकारी विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए 71,278 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया है, जिसमें देशी शराब के दाम बढ़ने से करीब 1,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान आएगा।

इन इलाकों का घटेगा कोटा

शहरी क्षेत्रों में देशी शराब की खपत कम होने के चलते इन इलाकों का कोटा घटाया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों का कोटा बढ़ाया जाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों में लो अल्कोहल स्ट्रेंथ वाले पेय जैसे बीयर, वाइन और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) के लिए बार लाइसेंस दिए जाएंगे। यह कदम पर्यटन और युवा उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

भांग की दुकानों का लाइसेंस भी महंगा

भांग की दुकानों की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि वाइन और कम तीव्रता वाले पेय पर प्रतिफल शुल्क कम कर दिया गया है। इन पर मात्र 0।1 प्रतिशत सांकेतिक ड्यूटी लगाई गई है, ताकि फल उत्पादक किसानों को आर्थिक लाभ हो सके। नीति का सबसे आकर्षक हिस्सा निर्यात प्रोत्साहन है। आबकारी आयुक्त डॉ। आदर्श सिंह के अनुसार, यूपी देश का पहला राज्य है जिसने आबकारी निर्यात नीति लागू की है। इससे एथनॉल, शराब और संबंधित उत्पादों का विदेशी बाजार में निर्यात बढ़ेगा।

बोतल भराई शुल्क, निर्यात पास फीस, फ्रेंचाइजी फीस और स्पेशल फीस को न्यूनतम स्तर पर लाया गया है। ब्रांड पंजीकरण और लेबल अनुमोदन के नियमों को शिथिल किया गया है। अन्य राज्यों को शीरा आधारित एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) के निर्यात पर फीस को 0।50 रुपये प्रति बल्क लीटर तक घटाया गया है। हेरिटेज मदिरा के निर्माण, टेस्टिंग टैवर्न और फुटकर बिक्री की अनुमति भी दी गई है।

और क्या होगा असर?

इस नीति से डिस्टिलरी, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात सेवाओं का विस्तार होगा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूपी की शराब की मौजूदगी मजबूत होगी, जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मदद करेगी। थोक कारोबार में मोनोपोली को रोकने के लिए नियमों में ढील दी गई है, और अब डिस्टिलरी या कोई भी कारोबारी इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। लाइसेंस फीस अब उठान के आधार पर ली जाएगी। सरकार का मानना है कि ये बदलाव शराब उद्योग को पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाएंगे, साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हालांकि, दाम बढ़ने से आम उपभोक्ताओं पर कुछ बोझ पड़ेगा, लेकिन निर्यात से होने वाले लाभ से इसे संतुलित किया जा सकेगा।

सदन में सीएम योगी ने की घोषणा, बढ़ाई जाएगी तीन तरह की कैटेगरी की पेंशन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान करीब 1.06 करोड़ निराश्रित महिलाओं, वृद्धों और दिव्यांगजनों की पेंशन धनराशि बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बजट में इसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन हम इसमें इजाफा करने जा रहे हैं। सीएम की घोषणा के बाद पेंशन की धनराशि 1000 हजार रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये होगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इसकी घोषणा की थी।

वहीं दूसरी ओर सीएम ने सदन में शंकराचार्य विवाद पर पहली बार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, सपा अध्यक्ष

बनकर क्या प्रदेश में घूम सकता है? शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और सम्मानित है। लेकिन हर काम नियम से होता है। सदन भी नियमों और परंपराओं से चलता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। हम सभी संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हैं।

कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं

मुख्यमंत्री का पद भी कानून से ऊपर नहीं है। विद्वत परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है। हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। माघ मेला में उस दिन 4.50 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कोई कहीं भी जाकर माहौल खराब नहीं कर सकता है। वह माघ मेला के निकास द्वार से जाने का प्रयास कर रहे थे। यह श्रद्धालुओं के जीवन को खतरे में डाल सकता था। वहां भगदड़ मच सकती थी। कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा आचरण कैसे कर सकता है। हम मर्यादित लोग हैं। कानून का पालन करना और करवाना जानते हैं।सपा सदस्यों से पूछा कि यदि वह शंकराचार्य थे तो आपने वाराणसी में उन पर लाठीचार्ज करने के साथ एफआईआर क्यों दर्ज कराई थी। सपा पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के प्रकरण में भी आपने ऐसा ही किया। लोगों को गुमराह करने के बजाय देश के बारे में सोचना शुरू कीजिए। सपा ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, मथुरा-वृंदावन में विकास का विरोध किया। सपा सरकार में थानों और जेलों में जन्माष्टमी मनाने से रोका गया। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा को रोका। रामभक्तों पर गोलियां चलवाई। मंदिर निर्माण रोकने के लिए अदालत में वकील खड़े किए। सीएम ने कहा कि सनातन आस्था को कोई कैद नहीं कर सकता है। प्रदेश के पुनर्जागरण के हमारे मॉडल में आस्था और विकास दोनों शामिल हैं। दीपोत्सव, रंगोत्सव जैसे कार्यक्रमों से करोड़ों लोग जुड़कर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। आस्था को सम्मान देने से प्रदेश की जीडीपी में इजाफा हुआ है।

अभिभाषण का विरोध मातृशक्ति का अपमान

सीएम ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण का मुख्य विपक्षी दल का आचरण मातृशक्ति का अपमान है। यह कार्यक्रम अचानक नहीं थोपा गया था। दलीय बैठकों में चर्चा हुई थी। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय से कहा कि आप श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए, ब्राह्मण और सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से हैं। आप सनातन की बात कर रहे थे, लेकिन इसके अनुरूप कार्य नहीं किया। सनातन धर्म की परंपरा में अपनी उम्र से बड़ी महिला को भी मां के समान सम्मान दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने हजारों साल पहले बताया था.. 'नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्राणं, नास्ति मातृसमा प्रिया', यानी मां के समान कोई छाया नहीं है, मां के समान कोई सहारा नहीं है, मां के समान कोई रक्षक नहीं और मां के समान कोई प्रिय नहीं है।

कोई भी शंकराचार्य नहीं लिख सकता, माहौल खराब करने का हक किसी को नहीं, कानून से ऊपर मैं भी नहीं : योगी

लखनऊ। सीएम ने सदन में शंकराचार्य विवाद पर पहली बार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, सपा अध्यक्ष बनकर क्या प्रदेश में घूम सकता है? शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और सम्मानित है। लेकिन हर काम नियम से होता है। सदन भी नियमों और परंपराओं से चलता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। हम सभी संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री का पद भी कानून से ऊपर नहीं है। विद्वत परिषद द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही शंकराचार्य बन सकता है। हर कोई खुद को शंकराचार्य नहीं लिख सकता। माघ मेला में उस दिन 4.50 करोड़ श्रद्धालु आए थे। कोई कहीं भी जाकर माहौल खराब नहीं कर सकता है। वह माघ मेला के निकास द्वार से जाने का प्रयास कर रहे थे। यह श्रद्धालुओं के जीवन को खतरे में डाल सकता था। वहां भगदड़ मच सकती थी। कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा आचरण कैसे कर सकता है। हम मर्यादित लोग हैं। कानून का पालन करना और करवाना जानते हैं।सपा सदस्यों से पूछा कि यदि वह शंकराचार्य थे तो आपने वाराणसी में उन पर लाठीचार्ज करने के साथ एफआईआर क्यों दर्ज कराई थी।

लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज, लखनऊ की छात्राओं ने विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही देखी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ में आयोजित बजट सत्र के दौरान लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा 11 की छात्राओं ने 11, 12 और 13 फरवरी को दर्शक दीर्घा में उपस्थित होकर सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया।शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत छात्राओं ने बजट प्रस्तुति की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा और सदन में जनहित से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चा तथा विचार-विमर्श को समझा। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। इस अवसर ने उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विधायी कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में व्यावहारिक समझ विकसित करने का अवसर प्रदान किया।सदन की कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरांत छात्राएं विधान भवन परिसर में उपमुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष के बाहर

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलीं। उपमुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद करते हुए उनके अनुभव सुने और उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग एवं सक्रिय रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर छात्राओं ने उनके साथ स्मृति चित्र भी खिंचवाए।उपमुख्यमंत्री ने इस शैक्षिक भ्रमण को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि ऐसे अनुभव युवाओं को जागरूक, उत्तरदायी और संवेदनशील नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विधानसभा की कार्यवाही का यह प्रत्यक्ष अनुभव छात्राओं के भविष्य के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

विधान परिषद में विजय बहादुर पाठक ने उठाया दूषित पेयजल का गंभीर मुद्दा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विजय बहादुर पाठक ने नियम 110 के अंतर्गत लोक महत्व का अत्यंत गंभीर विषय उठाते हुए प्रदेश में दूषित पेयजल की आपूर्ति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और शुद्ध पेयजल प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, किंतु वर्तमान में अनेक स्थानों पर गंदे और प्रदूषित पानी की आपूर्ति से जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। सभापति ने विषय की गंभीरता को देखते हुए इसे सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया।विजय बहादुर पाठक ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्यभर में अभियान चलाकर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, किन्तु स्थानीय निकायों के अधिकारियों की लापरवाही के कारण अनेक स्थानों पर दूषित जल की आपूर्ति हो रही है, जिससे स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इंदौर में हुई घटना के बाद मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में दूषित पेयजल की आपूर्ति न हो, इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं।उन्होंने गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक अनेक स्थानों पर गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा कि आजमगढ़ के आसिफगंज मोहल्ले में लोगों के घरों की टोटियों से नाले का गंदा पानी आने की शिकायत सामने आई। जांच में पाया गया कि नाली और सीवर के बीच से

लखनऊ में महापौर का जोन-8 निरीक्षण, खाली पड़ी निगम भूमि के सीमांकन व उपयोग के निर्देश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम के जोन-8 अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर तथा अंसल खेवली गांव का शुक्रवार को महापौर सुषमा खर्कवाल ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, डॉ. अरविंद कुमार राव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों की वर्तमान स्थिति का आकलन कर उनके संरक्षण और प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करना था।निरीक्षण के दौरान महापौर ने हरिहरपुर और खेवली गांव में नगर निगम की खाली पड़ी भूमि का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों से भूमि के स्वामित्व अभिलेख, सीमांकन, वर्तमान स्थिति और संभावित उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि निगम की सभी

खाली भूमि का शीघ्र सीमांकन कराकर तारबाड़ और बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो सके।महापौर ने कहा कि नगर निगम की संपत्तियों का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि इन भूमियों का योजनाबद्ध और राजस्व उन्मुख उपयोग किया जाए, जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने सुझाव दिया कि आवश्यकता के अनुसार इन स्थलों पर सामुदायिक सुविधाएं, पार्किंग स्थल, व्यावसायिक परिसर या अन्य राजस्व सृजन परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस संबंध में एक समग्र कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत की जाए।नगर आयुक्त गौरव कुमार ने महापौर को आश्वस्त किया कि सभी निर्देशों का समयबद्ध पालन कराया जाएगा।

स्वतंत्र देव सिंह ने किया सरदार वल्लभभाई पटेल सिंचाई भवन का लोकार्पण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उदयगंज स्थित सिंचाई विभाग मुख्यालय परिसर में नवनिर्मित सरदार वल्लभभाई पटेल सिंचाई भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जलशक्ति राज्यमंत्री राकेश निषाद, प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग अनिल गर्ग, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष इं. संदीप कुमार, प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन इं. अशोक कुमार सिंह सहित विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अन्य अभियंता एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।लोकार्पण के अवसर पर मंत्री ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह नया भवन सिंचाई विभाग के कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित, संगठित और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इससे विभागीय कार्यक्षमता में वृद्धि होगी और क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

पीजीआई पुलिस ने 24 घंटे में किया चोरी का खुलासा, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल व नकदी बरामद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के दक्षिणी जोन अंतर्गत थाना पीजीआई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का सफल अनावरण कर एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया ओप्पो मोबाइल फोन तथा 5000 रुपये नकद बरामद किए हैं। इस संबंध में थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 091/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस के तहत मुकदमा पंजीकृत है।पुलिस के अनुसार 11/12 फरवरी 2026 की रात्रि को आवास विकास कार्यालय रोड स्थित एक दुकान में अज्ञात व्यक्ति द्वारा घुसकर मोबाइल फोन और गल्ले में रखी नकदी चोरी कर ली गई थी। घटना के अनावरण के लिए थाना पीजीआई पुलिस टीम को सक्रिय किया गया। उपनिरीक्षक

परमानन्द सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल नन्दलाल पटेल और कांस्टेबल संदीप कुमार द्वारा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने वृंदावन योजना सेक्टर-09, चिरैया बाग, सेक्टर-11, सेक्टर-16, ग्राम इश्वरी खेड़ा, सेक्टर-12 सहित विभिन्न स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश की।इसी क्रम में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर सेक्टर-10 स्थित सीवेज प्लांट के सामने सड़क किनारे पुलिया के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रोहित यादव पुत्र स्वर्गीय पुत्तीलाल निवासी तकरोही थाना इन्दिरानगर, लखनऊ उम्र लगभग 28 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान उसकी पैंट की जेब से एक काले रंग का ओप्पो मोबाइल फोन तथा जैकेट की जेब से 5000 रुपये नकद बरामद हुए।कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह भाड़े पर वाहन चलाने का कार्य करता है और पिछले कुछ दिनों से वृंदावन पीजीआई क्षेत्र में ही आ-जा रहा था। पैसों के लालच में उसने 11/12 फरवरी की रात दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त सुनसान स्थानों को चिन्हित कर चोरी करता था।जांच में यह भी सामने आया कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी थाना गाजीपुर, लखनऊ में मु0अ0सं0 29/14 धारा 392 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने बरामद माल को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दक्षिणी जोन पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

महाशिवरात्रि पर लखनऊ में विशेष ट्रैफिक डायवर्जन, 14 फरवरी रात 12 बजे से लागू होगी व्यवस्था

लखनऊ। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 15 फरवरी 2025 को राजधानी के प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक यातायात व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। यह विशेष डायवर्जन व्यवस्था 14 फरवरी 2025 की रात्रि 12 बजे से आवश्यकतानुसार प्रभावी रहेगी, ताकि मनकामेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर सहित अन्य प्रमुख स्थलों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही सुचारु बनी रहे और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। जारी निर्देशों के अनुसार डालीगंज इक्का तांगा स्टैण्ड चौराहा से सामान्य यातायात मनकामेश्वर मंदिर बंधा रोड होते हुए हनुमान सेतु तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा। ऐसे वाहन आईटी चौराहा या डालीगंज पुल होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। मनकामेश्वर मंदिर ढाल तिराहा से मंदिर की ओर किसी भी प्रकार का यातायात प्रतिबंधित रहेगा। नदवा बंधा तिराहे से भी मनकामेश्वर मंदिर की दिशा में वाहन नहीं जा सकेंगे।

संक्षेप

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता–2026 का भव्य आगाज़, देशभर से 36 टीमें शामिल

लखनऊ(आरएनएस)। विश्वविद्यालय के विधि विभाग की स्पेक्ट्रा मूट कोर्ट समिति द्वारा आयोजित द्वितीय बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता–2026 का शुभारंभ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद उपस्थित रहे।समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अमरपाल सिंह तथा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजय तनेजा मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त विधि अध्ययन विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष प्रो. संजीव कुमार चड्ढा, विधि विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. सुदर्शन वर्मा सहित अनेक शिक्षकगण, शोधार्थी और विद्यार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए।कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन और बाबा साहेब के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। विश्वविद्यालय कुलगीत के उपरांत आयोजन समिति ने अतिथियों एवं शिक्षकों को पौधा भेंट कर स्वागत किया।कुलपति प्रो. राज कुमार मित्तल ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि उन्हें व्यावहारिक जीवन का अनुभव भी देना चाहता है। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा का उद्देश्य केवल कानूनों की जानकारी देना नहीं, बल्कि संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक संवेदनशीलता और न्याय के मूल्यों को आत्मसात कराना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्याय वितरण की प्रक्रिया में समाज के प्रत्येक वर्ग, उनकी पृष्ठभूमि और परंपराओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

बुनकरों के हित सर्वोपरि, विद्युत फ्लैट रेट योजना में बढ़ाया गया बजट: राकेश सचान

लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 में नियम 56 के अंतर्गत उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में ऊर्जा विभाग द्वारा फ्लैट रेट विद्युत आपूर्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे बाद में बकायेदारी बढ़ने पर हथकरघा विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार बुनकर प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद 1 अप्रैल 2023 से "अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना" लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरें निर्धारित की गई हैं। बुनाई कार्य में प्रयुक्त सहायक उपकरण जैसे बॉबिन, वार्पिंग, डबलिंग, बाइंडर मशीन और पंखा आदि को भी 5 किलोवाट की सीमा में शामिल किया गया है, जिससे बुनकरों को अतिरिक्त राहत मिल सके।उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 99,229 पावरलूम कनेक्शनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, जिनमें 92,869 कनेक्शन 5 किलोवाट श्रेणी के हैं। पूर्व में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर लगभग 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही 31 मार्च 2023 तक की बकाया विद्युत देनदारियों के भुगतान की जिम्मेदारी भी सरकार ने अपने ऊपर ली है।बजट 2026-27 में लगभग 4,423 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि हथकरघा विभाग पर लंबित लगभग 4,000 करोड़ रुपये की देनदारी का निस्तारण किया जा सके। मंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकरनगर और मेरठ मंडलों का दौरा कर बुनकरों से संवाद किया और उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए।उन्होंने दोहराया कि सरकार बुनकर समाज की कला, परंपरा और आजीविका की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रदेश सरकार बुनकरों और हस्तशिल्प से जुड़े लाखों परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है तथा उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पुलिस का मिशन शक्ति 5 .0 अभियान तेज, तालकटोरा में महिलाओं और छात्राओं को किया गया जागरूक

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना तालकटोरा क्षेत्र के सेक्टर-11 टैक्सी स्टैंड पर पिंक बूथ टीम ने भ्रमणशील होकर महिलाओं एवं छात्राओं को उनके अधिकारों, कानूनी प्रावधानों और साइबर अपराध से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।अभियान के दौरान छात्र-छात्राओं को डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने का संकल्प दिलाया गया और उन्हें बताया गया कि ऑनलाइन ठगी, उत्पीड़न और अन्य साइबर खतरों से कैसे बचा जा सकता है। उन्हें व्यावहारिक सुझाव दिए गए ताकि वे सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय सजग रहें। यह पहल नई पीढ़ी

को सशक्त बनाने और डिजिटल युग में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।मिशन शक्ति 5.0 के तहत पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ के 54 थानों में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक केंद्र पर निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला उपनिरीक्षक की तैनाती की गई है, जिससे थाने पर आने वाली महिलाओं की शिकायतों का त्वरित और संवेदनशील निस्तारण सुनिश्चित हो सके। पुलिस प्रशासन का उद्देश्य है कि महिलाएं बिना संकोच अपनी समस्याएं साझा करें और उन्हें समयबद्ध न्याय मिले।

कार्यक्रम में महिलाओं को विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी गई। उन्हें बताया गया कि 1090 महिला पावर लाइन पर उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, 112 पर किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस या अग्निशमन सहायता प्राप्त की जा सकती है, 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए, 1098 बच्चों से संबंधित समस्याओं के लिए, 1076 नागरिक सहायता के लिए और 1930 साइबर अपराध की शिकायत के लिए उपयोगी है। इसके अतिरिक्त यूपी कॉप मोबाइल अनुप्रयोग और साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई।मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम, कानूनी अधिकारों की जानकारी, शिक्षा के महत्व पर बल, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता तथा डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पिंक बूथ टीम द्वारा सीधे संवाद स्थापित कर महिलाओं को घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में आगे आकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

अनपरा तापीय परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित "गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ तापीय उत्पादन का सर्वोत्तम अनुकूलन" विषयक राष्ट्रीय सम्मेलन में अनपरा तापीय परियोजना को उत्पादकता में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान केंद्रीय विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल द्वारा दिया गया। इस उपलब्धि पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र के अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी है।संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पुनः मांग की है कि 2×800 मेगावाट क्षमता की अनपरा 'ई' परियोजना तथा 2×800 मेगावाट क्षमता की ओबरा 'डी' परियोजना को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को ही आवंटित किया जाए। समिति का कहना है कि जब राज्य क्षेत्र की उत्पादन इकाई को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जा रहा है, तब इन नई परियोजनाओं को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ संयुक्त उपक्रम में देने का कोई औचित्य नहीं है।समिति ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के ऊर्जा निगमों में उत्पादन, पारेषण और वितरण—सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि व्यापक सुधारों के परिणामस्वरूप प्रदेश में चौबीस घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।संघर्ष समिति के अनुसार यदि अनपरा 'ई' और ओबरा 'डी' परियोजनाएं संयुक्त उपक्रम के माध्यम से विकसित की जाती हैं, तो अलग आवासीय परिसर, कोयला प्रबंधन तथा राख प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं पर कई सौ करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा।

गड्ढों वाली व्यवस्था और खतरे में पड़ता जीवन

गड्ढों में गिरी व्यवस्था में समाप्त होता जीवन आज के भारत की एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर मन भीतर तक सिहर उठता है। नोएडा में कार सवार युवा इंजीनियर की गड्ढे में गिरकर मौत का दर्द अभी समाज के मन से उतरा भी नहीं था कि दिल्ली में बाइक सवार युवक की जान एक खुले गड्ढे ने लील ली। दोनों घटनाओं में समानता यह है कि गड्ढे प्रशासन द्वारा विकास या मरम्मत के नाम पर खोदे गए थे और दोनों जगह न तो कोई बैरिकेडिंग थी, न चेतावनी बोर्ड, न रोशनी की व्यवस्था। मानो व्यवस्था ने पहले गड्ढा खोदा और फिर निश्चिंत होकर वहां से हट गई कि अब जो होगा, वह नागरिक की किस्मत है। यही वह सोच है जो किसी भी समाज को भीतर से खोखला कर देती है।

प्रश्न यह नहीं है कि गड्ढे क्यों खोदे गए, प्रश्न यह है कि गड्ढे खोदकर लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का अधिकार प्रशासन को किसने दिया। क्या विकास का अर्थ यह हो गया है कि सड़कों पर चलते हुए हर नागरिक अपनी जान हथेली पर रखे। क्या शहरों की चमक-दमक और बड़े-बड़े दावों के बीच आम आदमी का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि उसकी मौत पर सिर्फ एक खबर छप जाए, दो दिन बहस हो और फिर सब कुछ सामान्य हो जाए। यह सामान्य हो जाना ही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब मौतें सामान्य लगने लगें, तब व्यवस्था की संवेदनशीलता मर चुकी होती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदा गया गड्ढा हो या नोएडा की किसी एजेंसी का, जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया हर बार एक जैसी रहती है। अफसर निलंबित कर दिए जाते हैं, जांच समितियां बना दी जाती हैं, 24 या 48 घंटे में रिपोर्ट देने की घोषणा होती है और कुछ समय बाद वही फाइलें धूल फांकने लगती हैं। निलंबन और जांच अब समाधान नहीं, बल्कि एक औपचारिक रस्म बन गई है। सवाल यह है कि क्या निलंबन से मरे हुए बेटे लौट आते हैं, क्या जांच समितियों से टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। जब तक जवाबदेही केवल कागजों पर सिमटी रहेगी, तब तक गड्ढों में गिरती जिंदगियां यूं ही व्यवस्था का शिकार बनती रहेंगी।

इस पूरी तस्वीर का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं कम से कम चर्चा में तो आती हैं, मीडिया सवाल तो उठाता है, लेकिन छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में यही गड्ढे रोज जिंदगियां निगल रहे हैं और खबर तक नहीं बनते। वहां न कैमरा पहुंचता है, न कोई प्रतिनिधि, न कोई जांच समिति। वहां मौतें सिर्फ परिवारों की निजी त्रासदी बनकर रह जाती हैं। क्या नागरिक का मूल्य शहर के आकार से तय होगा। क्या महानगरों का नागरिक ज्यादा कीमती है और छोटे शहरों का नागरिक सस्ता। यह असमानता केवल संसाधनों की नहीं, बल्कि संवेदनाओं की भी है।

हम एक ओर विकसित भारत, सशक्त भारत, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, दूसरी ओर हमारी सड़कों पर खुले गड्ढे हमें आईना दिखाते हैं। विकास की रफ्तार तेज हो सकती है, लेकिन यदि उस रफ्तार में सुरक्षा, जिम्मेदारी और मानवीय संवेदना नहीं जुड़ी, तो वह रफ्तार विनाश की ओर ही ले जाएगी। यह विडंबना ही है कि हम स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, लेकिन स्मार्ट बैरिकेडिंग, स्मार्ट चेतावनी और स्मार्ट जिम्मेदारी पर बात करना भूल जाते हैं। तकनीक के युग में भी एक साधारण चेतावनी बोर्ड लगाना हमारे तंत्र को याद नहीं रहता।

दरअसल समस्या केवल लापरवाही की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें नागरिक को एक आंकड़ा समझ लिया गया है। फाइलों में वह एक केस नंबर है, सड़क पर वह एक बाधा और हादसे के बाद वह एक आंकड़ा। जब तक प्रशासन और शासन की दृष्टि में नागरिक का जीवन सर्वोपरि मूल्य नहीं बनेगा, तब तक हर नया गड्ढा एक नई मौत की संभावना बनकर खड़ा रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या इन गड्ढों के लिए कभी उच्च स्तर पर नैतिक जिम्मेदारी तय होगी। क्या कभी ऐसा होगा कि किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से पूछा जाए कि आपके विभाग की लापरवाही से एक जान गई, इसलिए आप पद पर बने रहने के नैतिक अधिकारी नहीं हैं।

भ्रष्ट शासन के समाप्त होने की बड़ी-बड़ी घोषणाएं हर चुनाव में सुनाई देती हैं। पोस्टर बदलते हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन जमीन पर गड्ढे वैसे ही रहते हैं। यदि भ्रष्टाचार केवल रिश्वत लेने तक सीमित होता तो शायद उसे पहचानना आसान होता, लेकिन यह जो संवेदनहीन भ्रष्टाचार है, जहां नियमों की अनदेखी, सुरक्षा मानकों की उपेक्षा और समय पर काम पूरा न करना शामिल है, यह ज्यादा खतरनाक है। इसमें पैसा दिखता नहीं, लेकिन इसकी कीमत किसी की जान से चुकानी पड़ती है। आज जब हम अमृत काल और शताब्दी वर्ष में नए भारत की कल्पना कर रहे हैं, तब यह प्रश्न और भी तीखा हो जाता है कि क्या खुले गड्ढों वाला देश महान बन सकता है। क्या वह देश विकसित कहलाने योग्य है, जहां नागरिक रात को सड़क पर निकलते समय यह दुआ करे कि कहीं कोई गड्ढा उसकी जिंदगी न छीन ले।

संसद बनी बंधक- संविधान का अपमान कौन कर रहा है?

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हंगामा करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने के बाद जब समय आने पर राहुल गांधी को बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने विषय से इतर जाकर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक कोट करते हुए चीनी घुसपैठ का पुराना मुद्दा उछालने का प्रयास किया।

मृत्युंजय दीक्षित

वर्ष -2026 का बजट सत्र हल्ले-गुल्ले और अराजकता की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ बजट के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को उठाए जाने का प्रयास हो रहा है। स्थितियां इतनी विकट हैं कि संसदीय इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री लोकसभा में उत्तर नहीं दे सके और राष्ट्रपति का अभिभाषण बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। यद्यपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में 97 मिनट लंबा और प्रभावशाली उत्तर दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा की गई सभी टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन देश के स्वर्णिम भविष्य और विकास की दिशा को भी दर्शाता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय हंगामा करके देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करने के बाद जब समय आने पर राहुल गांधी को बोलने का अवसर दिया गया तो उन्होंने विषय से इतर जाकर पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक कोट करते हुए चीनी घुसपैठ का पुराना मुद्दा उछालने का प्रयास किया। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियमों के अंतर्गत व्यवस्था दिए जाने के बाद भी राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े रहे। यह एक आश्चर्यजनक व्यवहार है कि नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के स्थान पर पुराने मुद्दे उठाए और उनको भी आपत्तिजनक रूप से रखकर देश की सेना और सदन का अपमान करे। लोकसभा में कांग्रेस तथा इंडी गठबंधन की महिला सांसदों ने जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने की योजना बनायी और लोकसभा अध्यक्ष को प्रधानमंत्री से सदन न आने का अनुरोध करना पड़ा वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विडम्बना ये है कि यही लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बाते करते हैं।

राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग न लेकर विपक्षी दलों ने न केवल राष्ट्रपति पद का अपमान किया है अपितु एक गरीब परिवार से निकलकर आई आदिवासी महिला का भी अपमान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में राहुल गांधी व कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को ग़द्दार कहने पर भी राहुल गांधी घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनका अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच गया है । कांग्रेस छोड़कर कितने ही लोग निकले हैं किसी और को तो ग़द्दार नहीं कहा, ये सिख हैं इसलिए कहा, ये सिखों का, गुरुओं का अपमान था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोकसभा में चेयर पर कागज फेकें गए जब असम के सदस्य चेयर की कुर्सी पर विराजमान थे क्या यह असम का अपमान नहीं? जब आंध्र प्रदेश के एक दलित सदस्य चेयर की कुर्सी पर बैठे थे तब उन पर भी कागज फेंके गए क्या यह एक दलित बेटे और संविधान का अपमान नहीं है ?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आखिर कांग्रेस उनके लिए कब्र खुदेगी का नारा क्यों देती है ? हमने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 से हटाई इसलिए या हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उबारा है इसलिए? प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने के सपने देखती है? आजकल मोहब्बत की दुकान खोलने वाले "मोदी तेरी कब्र खुदेगी" के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। हमने नार्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो साया बना रहता था वहां शांति और विकास की राह अपनाई इसलिए वह मोदी की कब्र खोद रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियो को घर में घुसकर मारते हैं, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं और इसलिए वे मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये जो उनके भीतर नफरत भरी हुई है मोहब्बत की दुकान में जो आग भरी पड़ी हुई है, उसका कारण है किकांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि कोई और क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, ये तो हमारा पैतृक अधिकार था इसलिए वे हताशा में मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगे जोड़ा कि कांग्रेस को ये सहन नही हो रहा हे कि जो समस्याएं उसने 60 सालो में पाल- पोस कर बड़ी की थीं मोदी उनका एक-एक करके समाधान क्यों कर रहा है? कांग्रेस को ये सब पसंद नहीं आ रहा है इसलिए अब कांग्रेस के नेता मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा लगा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन और फिर अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौते हुए उनके विषय में जानकारी देते हुए बताया कि अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और समझौते कर रही है। कांग्रेस को भी यहअवसर मिला था, उन्होंने यह क्यों नही कर दिखाया? प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से कांग्रेस,लेफ्ट व डीएमके सहित टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला और उन्होंने बंगाल की टीएसमी सरकार को देश की सबसे निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि यह लोग अपने अंदर नहीं झाकते अपितु हमको यहां बैठकर उपदेश देते हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद सदानंद मास्टर के भाषण का संज्ञान लेते हुए वैचारिक सहिष्णुता की चर्चा की, ज्ञातव्य है कि सदानंद मास्टर के दोनों पैर वामपंथी विचारधारा के लोगों ने निर्ममता से केवल उनकी विचारधारा अलग होने के कारण काट दिए थे।

संसद के वर्तमान सत्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने जो रवैया अपनाया है उसने देश के वास्तविक मुद्दों को उठाने का एक सुनहरा अवसर खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा को घेरने के बजे उन्होंने भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी को ही अपने ऊपर आक्रमण करने का अवसर दे दिया है। भाजपा अब सिख व दलित सांसदों के अपमान का राजनैतिक लाभ उठाने का पूरा प्रयास करेगी। भाजपा चुनाव वाले राज्यों में विरोधी दलों के संसदीय आचरण को भी मुद्दा बनाएगी।

टिप्पणी

जन समस्याओं का हल सांत्वना का भ्रम

सालाना बजट आज महज वित्तीय विवरण, कर दरों में हेरफेर, खर्च के लक्ष्यों की घोषणा और जहां-तहां कुछ प्रोत्साहनों के एलान का दस्तावेज भर रह गया है। बुनियादी आर्थिक समस्याओं के हल की बात उसके दायरे से बाहर हो चुकी है।

कांग्रेस की राय में केंद्रीय बजट अर्थव्यवस्था की बुनियादी चुनौतियों से आंख मिलाने में नाकाम रहा। दरअसल, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तो यहां तक कहा कि वित्त मंत्री ने उन चुनौतियों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया। मसलन, अमेरिकी टैरिफ से कारखाना उत्पादकों और निर्यातकों के सामने आई चुनौतियों, व्यापार घाटे, निम्न ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एफडीआई की अनिश्चितता, राजकोषीय सेहत में सुधार की धीमी गति, महंगाई के सरकारी आंकड़ों एवं अनुभवजन्य स्थिति में फर्क, लाखों एमएसएमई इकाइयों के बंद होने, बेरोजगारी, और शहरी बुनियादी ढांचे में लगातार गिरावट पर निर्मला सीतारमन ने चुप्पी साध ली। ये आलोचना वाजिब है। यह हकीकत है कि आज सालाना बजट महज वित्तीय विवरण, कर दरों में हेरफेर, खर्च के लक्ष्यों की घोषणा और जहां-तहां कुछ प्रोत्साहनों के एलान का दस्तावेज भर रह गया है।

मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था जब असल में मोनोपॉली पूंजीवाद का रूप ले चुकी हो, तो बिना उस ढांचे को चुनौती दिए सरकारें अक्सर ढांचागत समस्याओं का हल निकालने में अक्षम हो जाती हैं। नतीजतन, बजट के जरिए शायद ही बाजार में मांग और निजी निवेश की स्थितियां बनाई जा सकती हैं। बिना ऐसा हुए ना तो रोजगार सृजन संभव है, और ना ही मानव विकास या रहन-सहन की बेहतर सूरत बनाना। देसी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं नहीं होगी, तो भारतीय उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में टिकने की बात महज एक खामख्याली ही है। बाकी जहां तक व्यापार घाटा, पर्याप्त मात्रा में एफडीआई ना आना या पोर्टफोलियो इन्वेस्टरों के भारत से पैसा निकालने, या रुपये की कीमत मे गिरावट की बात है, तो वे जारी हालात के नतीजे हैं। यथार्थ तो यह है कि लगातार अपनी ताकत कॉरपोरेट सेक्टर को ट्रांसफर करती गई सरकार की अब ऐसे मसलों का हल ढूंढने की काबिलियत अब काफी हद तक क्षीण हो चुकी है। इस हाल में आबादी के कुछ समूहों को नकदी हस्तांतरण कर चुनावी लाभ की योजनाएं शुरू करने से आगे कुछ करने को वह सोच नहीं पाती। उन योजनाओं के जरिए जन समस्याओं का हल करने की सांत्वना का भ्रम वह पैदा करती है। इस बार भी वह इतना ही कर पाई।

ब्लॉग

कृषि उपज के लिए बाजार को खोलना यानी बवंडर को निमंत्रण

उमेश चतुर्वेदी

इसमें दो राय नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका बरसों से भारतीय कृषि बाजार में बड़ी और व्यापक पहुंच हासिल करने की कोशिश में है। हाल ही में अमेरिका के साथ भारत ने महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है। इसके तहत अमेरिकी बाजारों में भारतीय सामान 18 प्रतिशत के ही टैरिफ पर उपलब्ध हो सकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय सामानों पर मनमाने तरीके से थोपे गए पचास प्रतिशत के टैरिफ के मुकाबले मौजूदा व्यापार समझौते के तहत अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 18 प्रतिशत का टैरिफ कम ही कहा जाएगा। हालांकि अतीत के करीब तीन प्रतिशत के मुकाबले फिर भी यह बहुत ज्यादा है। बहरहाल इसी समझौते के मद्देनजर जिस तरह से अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक लेस्ली रोलिंग्स ने खुशी जताई, उससे भारतीय किसान आशंकित हो उठे।

भारतीय किसानों के आशंकित होने की वजह रोलिंग्स का बयान ही नहीं, अमेरिकी कृषि विभाग की कोशिशें भी हैं। रोलिंग्स ने व्यापार समझौते पर तीन फरवरी को एक्स पर खुशी जताते हुए लिखा कि यह समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार में अधिक निर्यात करने में मदद करेगा, जिससे अमेरिकी कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण अमेरिका में नकदी आएगी। रोलिंग्स यहीं पर नहीं रूके। उन्होंने सिर्फ 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि भारत के साथ कृषि कारोबार के चलते अमेरिका को 1.3 अरब डॉलर का घाटा हो रहा है। रोलिंग्स ने उम्मीद जताई कि नए व्यापार समझौते की वजह से विशाल आबादी वाला भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण बाजार हो सकता है।

रोलिंग्स की इस खुशी की वजह से भारतीय किसानों का आशंकित होना जायज है। अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा पचास अरब डॉलर है, इसलिए वह लगातार कोशिश करता रहा है कि भारत अपने कृषि बाजारों को खोले। भारत की चिंता की वजह उसकी खेती-किसानी वाली बड़ी जनसंख्या है। भारत के छियासी प्रतिशत किसान सीमांत या लघु हैं। जिनकी जोत दो हेक्टेयर से कम है। भारत में खेती पर करीब 10.7 करोड़ परिवार निर्भर हैं। यह जनसंख्या का करीब बासठ प्रतिशत है। अगर अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजारों में घुसने की अनुमति मिलती है तो भारी सब्सिडी के चलते भारतीय बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों से भर जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग घट सकती है। इससे भारतीय किसानों के सामने संकट उठ खड़ा हो सकता है।

किसानों की आशंकाओं को विपक्षी दलों ने अपने ऊंचे सुरों से और बढ़ाया ही है। लेकिन कृषि, किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि भारत-अमेरिकी व्यापार समझौते में भारतीय कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है और किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं। चौहान का यह भी कहना है कि इस कारोबारी समझौते से देश के मुख्य खाद्यान्नों, मिलेट्स, फलों,सब्जियों और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह अलग रखा गया है। इस लिहाज से देखें तो इस कारोबार समझौते से देश के कृषि और डेयरी क्षेत्र पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक, इस समझौते से भारतीय किसानों को नए अवसर मिलेंगे,क्योंकि इस समझौते में कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, भारत की ओर से अमेरिका समेत कई देशों को करीब 63 हजार करोड़ के चावल का निर्यात कर चुका है। भारत सरकार का दावा है कि नए टैरिफ समझौते से भारतीय किसानों के चावल और मसालों के साथ ही टेक्सटाइल का निर्यात बढ़ेगा।

भारत-अमेरिकी समझौते के तहत भारत को अमेरिका से पांच सौ अरब डॉलर का सामान पांच सालों में खरीदना है। वैसे समझौते पर जो संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है, उसके तहत भारतीय कृषि बाजार को भी खोलने की बात कही गई है। लेकिन सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस समझौते से, भारतीय चावल, गेहूं, सोया और मक्का जैसे अनाजों को बाहर रखा गया है और साथ ही ट्रेड डील से चीनी और डेयरी प्रोडक्ट्स भी बाहर हैं। ऐसा करने की वजह यह है कि भारतीय किसान और डेयरी उद्योग को कारोबारी परेशानियां न झेलनीं पड़ें। वैसे भी भारत लंबे समय से कृषि और डेयरी उद्योग को 'रेड-लाइन' यानी किनारे रखने वाला सेक्टर मानता रहा है। इसकी वजह है कि गांवों में इनसे जुड़े काफी रोजगार हैं। इन सेक्टर को खोलने को लेकर भारत की बातचीत यूरोप और ब्रिटेन से भी अटक चुकी है। ऐसे में अमेरिका के लिए इस बाजार को खोलना भारतीय किसानों के लिए नुकसानदायक तो होगा ही, राजनीतिक बवंडर की वजह भी बन सकता है। इस बवंडर का सामना करने की हिम्मत विरली राजनीतिक ताकतें ही कर सकती हैं। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, खासतौर पर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए तीन लाख अरब अमेरिकी डॉलर का बड़ा बाजार खुलने की उम्मीद है। इसकी वजह से जो निर्यात बढ़ेगा, उससे महिलाओं और युवाओं के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना जताई जा रही है। भारत मक्का, गेहूं, चावल, सोया, मुर्गी पालन, दूध, पनीर, एथनॉल, तंबाकू, सब्जियां और मांस सहित संवेदनशील कृषि और दुग्ध उत्पादों को पूर्ण रूप से संरक्षित करेगा। दोनों देश अपने-अपने हित वाले क्षेत्रों में एक-दूसरे को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं।

आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में भारत ने अमेरिका से 2.4 अरब डॉलर के कृषि उत्पाद आयात किए थे, जिनमें ज्यादातर ताजे फल, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट मादक पेय, कच्चा कपास, वनस्पति तेल और प्रोसेस्ड सामान हैं। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को 6.2 अरब डॉलर का कृषि निर्यात किया, जिनमें समुद्री उत्पाद, मसाले, डेयरी उत्पाद, चावल, जड़ी-बूटियों के आयुर्वेदिक उत्पाद प्रमुख रहे। यह भारत के कुल 53.2 अरब डॉलर सालाना के कृषि निर्यात का 11.74 प्रतिशत है। कृषि और डेयरी उत्पाद के कारोबार के इसी असुंलन की वजह से अमेरिका भारतीय बाजार में घुसने की लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सूत्र इससे साफ इनकार कर रहे हैं। भारत के सामने संकट यह है कि अगर उसने इस क्षेत्र को खोला तो छोटे और सीमांत किसानों के सामने जो चुनौतियां खड़ी होंगी, उनसे वह कैसे निबट पाएगा।

सुहागरात पर दुल्हन बोली- मुझसे दूर रहना वरना गंवानी पड़ेगी जान, ढाई महीने घुटता रहा दूल्हा, अब थाने पहुंचा

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कहते हैं कि शादी की पहली रात खुशियों की सौगात लाती है, लेकिन साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में दूल्हे के दिल पर उस वक्त आघात पहुंचा। जब नई नवेली दुल्हन ने सुहागरात के समय पति से दूर रहने की बात कही। करीब ढाई महीने तक युवक कड़वा घूट पिए अंदर-अंदर ही घुटता रहा।

बीते बुधवार को युवक ने दूल्हन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने जिंदगी से हाथ धो बैठोगे की धमकी देकर कमरा बंद करके फंदा लगा लिया। ससुरालीजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे बचा लिया। घटनाक्रम के बाद घबराया युवक गुरुवार को साढ़ थाने पहुंचकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।

प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी दुल्हन

महाराजपुर थाना अंतर्गत एक गांव की युवती की शादी बीते 23 नवंबर को साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से हुई थी। बरात विदा होने के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन ने सुहागरात में पति से दूर रहने की बात कही। इसके बाद प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ी दुल्हन ने पति को जिंदगी से हाथ धो बैठने की भी धमकी दे डाली।

दरवाजा बंद कर फंदा लगाया

युवक के मुताबिक बीते बुधवार को फिर समझाने का प्रयास किया, तो पत्नी ने जल्द ही अंजाम भुगत लेने की धमकी दे दी। इसके बाद दरवाजा बंद कर फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। किसी तरीके से दरवाजा तोड़कर उसे बचाया जा सका।

पुलिस ने दोनों परिवारों को बुलाया

दुल्हन के तेवरों से डरा सहमा युवक साढ़ थाने पहुंचा और पुलिस को अपनी व्यथा सुनाई और दुल्हन की धमकी के कुछ सबूत भी सुनाए। साढ़ प्रभारी निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह ने बताया दोनों परिवारों को बुलाकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है।

मुरादाबाद शुगर मिल में 'मौत' का ड्रामा! भाई बोला- मेरे सामने कट गया अरविंद, सदमे में था परिवार

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित दीवान शुगर मिल में कर्मचारी के मिल की चेन से कटकर मौत का संदिग्ध मामला सामने आया था। इसके बाद मृतक बताए गए कर्मचारी अरविंद के परिजनों ने मिल के कर्मचारियों की लापरवाही से मौत का आरोप लगाया था। परिजनों का कहना था कि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अरविंद की मिल की चेन में कटकर मौत हो गई।

इसके बाद पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच की तो मामला बेहद चौंकाने वाला सामने आया। अरविंद जिंदा निकला और वह घर पर मौजूद मिला। पुलिस ने अरविंद को घर से बरामद कर लिया है।

मझोला थाना इलाके के गांव बहलोलपुर निवासी मजदूर अरविंद कुमार सिविल लाइन के अगवानपुर स्थित दीवान शुगर मिल में काम करता था। मंगलवार रात वह मिल की चेन के पास ड्यूटी कर रहा था, उसी समय वह गायब हो गया। उसके भाई जितेंद्र ने दावा किया कि अरविंद उसकी आंखों के सामने चलती चेन में गिर गया और कटकर उसकी मौत हो गई।

घटना को लेकर बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों ने मिल में जमकर हंगामा किया और चेन के अंदर धरने पर बैठ गए। परिजनों ने मिल प्रशासन पर आरोप लगाए थे कि मिल वालों ने चेन नहीं रोकी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एडीएम सिटी ज्योति सिंह और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह भी पहुंच गए। कई थानों की फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। पुलिस ने किसी तरह समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। इस दौरान करीब 9 घंटे तक मिल बंद रही।

शाम को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। सिविल लाइन पुलिस मामले में जांच-पड़ताल कर रही थी। इसी बीच तड़के नाटकीय घटनाक्रम में अरविंद अपने घर लौट आया, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सिविल लाइन पुलिस उसे थाने लाकर पूछताछ कर रही है।

अरविंद ने बताया कि वह मिल में गिर गया था, उसके बाद किसी तरह निकलकर बाग में चला गया था। वहां होश में आने के बाद वह घर लौट आया।

पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शुगर मिल में काम करने वाले एक मजदूर ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने भाई के गायब होने की सूचना दी थी। मजदूर ने यह भी आरोप लगाया था कि उसका भाई चेन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो गया। परिजनों ने प्रदर्शन भी किया। हमें जो अंदेशा था, वह सही निकला। सुबह अरविंद घर पर मिला। पुलिस उसे थाने ले आई है और पूछताछ की जा रही है।

'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के तहत पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित

आर्यावर्त संवाददाता

गोण्ड। "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को स्थानीय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) के सहयोग से पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की गयी। डायरिया के प्रति जागरूकता के लिए इस मौके पर रोल प्ले का भी आयोजन किया गया। प्रिंसिपल गीता त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में 39 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें कक्षा-10 की अर्पिता पहले, कक्षा-10 की ज्योति दूसरे और कक्षा -10 की ही नेहा तीसरे स्थान पर रहीं। कक्षा-9 की अंजली को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। रोल प्ले में कक्षा-10 की रागिनी और वैष्णवी अव्वल रहीं।

इस मौके पर प्रिंसिपल ने डायरिया रोकथाम और प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि बच्चे को दिन में तीन बार से अधिक पतली दस्त हो, प्यास ज्यादा लगे और आँखें धंस गयी हों तो यह डायरिया के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे को जल्दी से जल्दी ओआरएस का घोल देना शुरू करें और तब तक इस घोल को देते रहें जब तक की दस्त ठीक न हो जाए। इसके साथ ही निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से सम्पर्क करना चाहिए। इसके अलावा स्थानीय एएनएम या आशा दीदी के सहयोग से जिंक की गोली प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा बताये गए तरीके से 14 दिनों तक बच्चों को अवश्य दें। डायरिया की चपेट में कई कारणों से बच्चे आ सकते हैं, जैसे- दूषित जल पीने से, दूषित हाथों से भोजन बनाने या बच्चे को खाना खिलाने, खुले में शौच करने या बच्चों के मल का ठीक से निस्तारण न करने आदि से। इसलिए डायरिया से बचाव के लिए घर और आस-पास साफ-सफाई रखें। शौच और बच्चों का मल साफ़ करने के बाद, भोजन बनाने और खिलाने से पहले हाथों को साबुन-पानी से अच्छी तरह अवश्य धुलें।

इस अवसर पर पीएसआई इंडिया से पंकज पाठक एवं अवध कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विद्यालय की ओर से शिक्षिका मनीषा, शालिनी, प्रमिला तिवारी, शहनाज आदि मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन मनोज मिश्रा ने किया।

पवन प्रकाश बने प्रदेश शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष

जौनपुर। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ, उ0प्र0 की प्रदेश कार्यकारिणी ने शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे पवन प्रकाश श्रीवास्तव को महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। संघ द्वारा जारी मनोनयन पत्र के अनुसार श्री श्रीवास्तव को जौनपुर जनपद का उपाध्यक्ष मनोनीत करते हुए जौनपुर सदर तहसील का प्रभारी नियुक्त किया गया है।प्रदेश संगठन मंत्री सुशील सिन्हा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि शिक्षा क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्यों एवं सक्रिय सहभागिता को देखते हुए यह जिम्मेदारी प्रदान की गई है। उनसे अपेक्षा की गई है कि तहसील अंतर्गत सभी ब्लॉकों में एक माह के भीतर योग्य, कर्मठ शिक्षकों, कर्मचारियों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रबंधकों का चयन कर जनपद एवं प्रदेश कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तावित करेंगे।पत्र में यह भी उल्लेख है कि वे जनपद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उनके समाधान के लिए संघर्ष करेंगे।

बनारस कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, जिला जज के ई-मेल पर आई सूचना, खाली कराया गया परिसर

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब जिला जज के ई-मेल पर कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसकी जानकारी मिलते ही बार पदाधिकारियों ने बैठक की। वहीं कचहरी परिसर में गहमागहमी का माहौल हो गया। रात 1.30 बजे ई-मेल पर धमकी भरा मैसेज आने की जानकारी मिली है। जिला जज को ई-मेल पर मिली धमकी के बाद कचहरी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार और कैंट इंस्पेक्टर शिवाकांत मिश्रा फोर्स और बम निरोधक दस्ते के साथ कचहरी में चेकिंग अभियान चला रहे हैं।

सेंट्रल बार अध्यक्ष प्रेमप्रकाश सिंह गौतम ने बताया कि जिला जज ने दोनों बार के अध्यक्ष महामंत्री को

अपने चैंबर में बुलाकर जानकारी दी कि उनके यहां ई-मेल आया है, जिसमें डेढ़ बजे आतंकवादी संगठनों ने कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी है। ऐसे में सभी मामलों में तारीखें दी जा रही हैं और कचहरी खाली करने का अनुरोध किया गया है।

प्रभावी प्रस्तुति से ही खुलते हैं कॉरपोरेट के द्वार

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के केंद्रीय प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में शुक्रवार को आर्यभट्ट सभागार में 'अकादमिक-उद्योग संवाद' का आयोजन किया गया। "साक्षात्कार कैसे देंरू कौशल, तैयारी और आत्मविश्वास" विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में देश-विदेश के विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को कॉरपोरेट जगत की चुनौतियों का सामना करने और साक्षात्कार में सफलता पाने के गुर सिखाए।कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (ठ।त्ब्) के वैज्ञानिक अधिकारी श्री विनोद कुमार मिश्रा ने छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि साक्षात्कार में अभ्यर्थी के ज्ञान और कौशल के प्रदर्शन में भाषा कभी बाधक नहीं होती। उन्होंने कहा, साक्षात्कार लेने वाले की अपेक्षा होती है कि अभ्यर्थी अपने ज्ञान को कम समय में सटीक रूप से प्रस्तुत करे, ताकि आपसी बातचीत के लिए अधिक समय मिल सके और व्यक्तित्व का सही आकलन हो सके।

हाथरस सत्संग हादसा : तत्कालीन एसडीएम की हुई गवाही, मामले में हैं 676 गवाह, 121 लोगों की हुई थी मौत

आर्यावर्त संवाददाता

हाथरस। हाथरस अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में 12 फरवरी को तत्कालीन एसडीएम रविंद्र कुमार की गवाही हुई। न्यायालय ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि नियत की है। उल्लेखनीय है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के दो जुलाई 2024 को सिकंदराराऊ तहसील के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग में भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 250 लोग घायल हुए थे। न्यायालय में पुलिस ने इस मामले में 11 आरोपियों के विरुद्ध 3200 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में पुलिस ने 676 गवाह बनाए हैं। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य और दलवीर सिंह पर मुकदमा चल रहा है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक महेंद्र श्रीवास्तव के न्यायालय में हो रही है।

चोरों का आतंक, पुलिस खानापूर्ति तक सीमित

जौनपुर। सांसद रविकिशन के थानागद्दी स्थित पैतृक गांव बराई में चोर वारदात के बाद आराम से निकल लेते हैं। फिर कुछ दिन शान्त रहने के बाद दूसरी वारदात को अंजाम देते हैं। बताते है कि गुरुवार की रात में आशीष सिंह के घर में घुसकर चोरों ने घर को खंगाला। पीड़ति के मुताबिक लगभग लाख रुपए के आभूषण व तीस हजार रुपए को समेटकर चलते बने। घटना की सूचना सुबह परिजनों ने पुलिस को दी। पीड़ति ने बताया कि सूचना के बाद दो सिपाही मौके पर पहुंचे,आगे पीछे घूम के जो कि लगभग कोरम पूरा करके चले गए। पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ति परिवार दहशत में हैं। परिवार का कहना है कि अब सुरक्षित तो नहीं महसूस रहे हैं। पुलिस के उदासीन रवैए के कारण ही चोरों के हौसले बुलंदी पर हैं। पुलिस के इस रवैए से मन व्यथित हैं।बीते साल चोरों के जयहिंद सिंह के घर में घुसकर कीमती जेवरात सहित लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए।

संगीत सोम बोले- कपसाड़ कांड ने बता दिया कि हम जाति-समुदाय के नाम पर नहीं करते राजनीति, ये सपा का काम

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि उनकी पार्टी जातियों के हक की बात करती है। समाज को बांटने का काम नहीं करती। उन्होंने विपक्षी पार्टी के उन प्रयासों की भी आलोचना की, जिसमें कपसाड़ में हुई महिला की हत्या को जातीय घटना बनाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि आगामी एक मार्च को होने वाले होली मिलन समारोह में विधानसभा के करीब 80 हजार लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा।

होली मिलन के आयोजन के संबंध में आयोजित बैठक में संगीत सोम ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हमेशा सच्चाई और न्याय की रही है, न कि किसी भी घटना को जाति या समुदाय के नाम पर भड़काकर राजनीति करने की। समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी संगठन जाति देखकर धरना देते हैं, जबकि हमारी पार्टी सभी वर्गों और समुदायों के साथ न्याय सुनिश्चित करने पर जोर देती है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव विकास कार्यों के बल पर लड़ा जाएगा लेकिन जातियों को बांटने का काम नहीं किया जाएगा। सरधना विधानसभा में सलावा में मेजर ध्यानचंद राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में सुधार होगा। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हरपाल सैनी ने भी विचार व्यक्त किए।

संक्षेप

ट्रक की चपेट में आने से युवक की मौत

जौनपुर। चंदवक थाना क्षेत्र के बाजार में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा घर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि घायल का उपचार प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि पड़ोसी जनपद आजमगढ़ लालगंज थानाक्षेत्र के बेरी डीह गांव निवासी आयुष उर्फ आवेश उम्र लगभग 20 वर्ष पुत्र कमलेश इस गांव का निवासी फतह 24 वर्ष पुत्र आलम गुरुवार रात्रि वाराणसी से बाइक द्वारा घर जा रहे थे। इसी दौरान चंदवक बाजार के पास ट्रक की चपेट में आ गए जिसके चलते दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।स्थानीय लोगों के सहयोग से जिला अस्पताल लाया जा रहा था कि आयुष की मौत हो गई। वहीं घायल का इलाज नर्सिंग होम में चल रहा है। घटना रात 10 बजे के करीब बताई गई है।

विकलांग युवती का रिस्की आपरेशन हुआ सफल

जौनपुर। नगर के लाइफ लाइन हास्पिटल पचहटिया में एक विकलांग और कमजोर युवती का आपरेशन कर चिकित्सक ने सराहनीय कार्य को अंजाम दिया है। इसकी चर्चा चिकित्सा जगत में हो रही है। बताते है कि जफराबाद क्षेत्र के पिडरा गांव की 35 वर्षीया सिन्दू पुत्री प्रो0 आसाराम पूरी तरह से विकलांग है। इसके गाल ब्लाडर में स्त्रोन था और वह असहनीय दर्द के दौर से गुजर रही थी लेकिन हाथ पैर निहायत कमजोर होने के कारण आपरेशन रिश्की बताया जा रहा था लेकिन लाइफ लाइन हास्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डा0 राजेन्द्र प्रसाद बिन्द ने अपने सहयोगी डा0 महेन्द्र प्रसाद अन्य स्टाफ के सदस्यों के साथ सिन्दू का सफल आपरेशन कर गाल ब्लाडर से स्त्रोन के 12 टुकड़े निकालकर युवती को जीवन भर के दर्द से राहत पहुंचा। आपरेशन के बाद युवती के पिता प्रो0 आसाराम ने कहा कि इस अस्पताल से गरीब कभी निराश हो कर वापस नहीं जाते कभी अस्पताल के संचालक डा0 राजेन्द्र बिन्द रूपये की चिन्ता नहीं करते सभी की सेवा समान रूप से करते है।

डूबे युवक का नहीं मिला सुराग

जौनपुर। शहर के सद्भावना पुल के पास स्थित गोपी घाट पर एक युवक के डूबने की आशंका से हड़कंप मच गया है। घटना को 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल सका है। परिजन उसकी तलाश में जुटे हैं, जबकि पुलिस भी मामले की जांच कर रही है।बताते है कि 25 वर्षीय मोहम्मद उस्मान पुत्र मोहम्मद जीशान, निवासी मोहल्ला तारापुर, कोतवाली थाना क्षेत्र, घर से निकले थे। काफी देर तक घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद कोतवाली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। तलाश के दौरान परिजन गोपी घाट पहुंचे, जहां दुकानदारों ने बताया कि दोपहर के समय एक युवक नदी में नहाते हुए डूब गया था। उस समय घाट पर सन्नाटा था, जिससे तत्काल राहत कार्य शुरू नहीं हो सका। यह जानकारी मिलते ही परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

हादसे में युवक की मौत, दूसरा गंभीर

जौनपुर। मुंगराबादशाहपुर। थाना क्षेत्र के प्रयागराज जौनपुर राजमार्ग पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा हसनपुर गांव के पास रात लगभग पौने एक बजे उस समय हुआ जब बोलोरो जीप प्रयागराज से जौनपुर की ओर जा रही थी। अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी पक्की दीवार से जोरदार टक्कर मार बैठा। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलोरो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए। हादसे में बोलोरो सवार विपिन पांडेय (30) पुत्र बृजेश पांडेय निवासी हरखमलपुर थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ में बैठे शुभम सिंह (20) पुत्र राजबीर सिंह, निवासी ग्राम भीदीयुरा, थाना बक्शा, जनपद जौनपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद वाहन में फंसे युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक विपिन पांडेय की सांसें थम चुकी थीं।

गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर हमला

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। बक्शा थाना क्षेत्र के बीरभानपुर गांव में गुरुवार की रात वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए गई एसओजी व पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। पथराव में एसओजी के जवानों सहित एक उपनिरीक्षक घायल हो गए, जबकि बक्शा थानाध्यक्ष की गाड़ी का शीशा भी टूट गया। घटना के बाद जिले के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंचकर गांव में घेराबंदी कर दी है।ज्ञात हो कि सिकरारा थाने के इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह एसओजी टीम के साथ रात करीब साढ़े नौ बजे बक्शा थाना क्षेत्र के बीरभानपुर गांव की अनुसूचित बस्ती में वांछित अभियुक्त पंकज गौतम की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे थे। पुलिस टीम के पहुंचते ही कुछ ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते ईंट-पत्थर चलने लगे। अचानक हुए

हमले से पुलिस टीम को संभलने का मौका नहीं मिला।पथराव में एसओजी के सिपाहियों के अलावा सिकरारा थाने में तैनात उपनिरीक्षक विनोद सिंह के घायल होने की सूचना है। घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है।सूचना मिलते ही बक्शा थानाध्यक्ष विक्रम लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे, लेकिन उग्र ग्रामीणों ने उनके वाहन पर भी पथराव कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया।घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर करीब आधा दर्जन से अधिक थानों की पुलिस फोर्स गांव में पहुंच गई है और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस हमलावरों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी में जुटी है।

भीषण सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत, खड़े ट्रक में पीछे से टकराई तेज रफ्तार कार

आर्यावर्त संवाददाता

सुलतानपुर। वाराणसी-लखनऊ हाईवे पर लंभुआ के मदनपुर पनियार स्थित पेट्रोल पंप के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में घायल मां-बेटे की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 4:30 बजे तेज रफ्तार कार के ट्रक में पीछे से भिड़ने के चलते हादसा हुआ है।

हादसे के बाद ट्रक लेकर चालक भाग निकला। हादसे के तुरंत बाद, सभी घायलों को तत्काल सीएचसी लंभुआ ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद, बेबी मसीह (45) और उनके पुत्र अर्पित कुमार (20) की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां इलाज के दौरान दोनों मां-बेटे ने दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान बेबी मसीह (45) और अर्पित कुमार (20) के रूप में हुई है। वे अमहर दक्षिण पट्टी माधवपुर, थाना रसड़ा, जनपद बलिया के निवासी थे और वर्तमान में अपनी नानी के घर रह रहे थे। उनके परिवार का पैतृक घर मुजफ्फरपुर में बताया गया है।

लड़का या लड़की, हर किसी को पसंद आएंगे ये गिफ्ट, वैलेंटाइन के लिए बेस्ट

वैलेंटाइन डे पर पार्टनर को स्पेशल फील करवाने के लिए गिफ्ट भी दिए जाते हैं। कई बार लड़के जब तोहफा खरीद रहे होते हैं तो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है कि लड़कियों के हिसाब से क्या देना सही रहेगा। इसी तरह से लड़कियां भी सोचती हैं। यहां पर कुछ ऐसे गिफ्ट्स दिए गए हैं जो लड़का और लड़की दोनों को ही खूब पसंद आते हैं।

परफ्यूम सेट

वैलेंटाइन डे पर परफ्यूम गिफ्ट करना एक कमाल का आइडिया है। इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। ये लड़का हो या लड़की सभी के काम आने वाला प्रोडक्ट है। बस आप अपने पार्टनर की पसंद के फ्रेगरेंस का ध्यान रखें या फिर वह जिस ब्रांड का परफ्यूम यूज करते हैं वो गिफ्ट कर दें।

पोलो टी-शर्ट्स

पोलो टी-शर्ट भी लड़कियां और लड़के दोनों ही पहनते हैं, क्योंकि ये काफी कंफर्टेबल होती हैं और डेली रूटीन के लिए बढ़िया रहती है। आप अपने पार्टनर के लिए पोलो टी शर्ट ले सकते हैं। बस आपको उनकी पसंद के रंग और टीशर्ट के साइज का ध्यान रखना होगा।

हेडफोन करें गिफ्ट

हेडफोन भी एक ऐसी चीज है जो लड़का और लड़की दोनों को ही गिफ्ट की जा सकती है। तो फिर इंतजार किस बात का है। इस वैलेंटाइन आप अपने लव वन के लिए किसी अच्छे ब्रांड का हेडफोन खरीदकर दे सकते हैं।

हेयर केयर प्रोडक्ट

वैलेंटाइन डे के लिए अगर ऐसे गिफ्ट की बात करें जो लड़का और लड़की दोनों के लिए बेस्ट रहे तो आप अपने लव पार्टनर को हेयर केयर प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हैं। इसमें कॉम्ब के अलावा हेयर सीरम, हेयर ऑयल, कोई अच्छा शैंपू,हेयर सेट करने वाला स्प्रे जैसी चीजें इस कॉम्बो सेट में शामिल कर सकते हैं।

की-चेन करें गिफ्ट

वैलेंटाइन डे पर की-चेन भी गिफ्ट की जा सकती है जो बजट फ्रेंडली गिफ्ट भी है। आप अपने और पार्टनर के लिए नाम के अक्षर वाली कस्टमाइज की-चेन ले सकते हैं। अगर आपके पार्टनर घर लेने वाले हैं तो आप होम लिखी हुई की-चेन के साथ उन्हें सरप्राइज कर सकते हैं। लड़कों के लिए बाइक के डिजाइन वाली की-चेन काफी अच्छी रहती हैं।

छोड़ देंगे दूसरों से प्यार और सहारे की उम्मीद, अगर सीख लेंगे Self Love से जुड़ी 10 आदतें

हम अक्सर दूसरों से प्यार की उम्मीद में अपनी खुद की इच्छाओं को दबा देते हैं, लेकिन यह समझना बेहद जरूरी है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक दूसरों से प्यार पाना मुश्किल होगा। कई लोगों को खुद से प्यार करने की बजाय दूसरों को प्यार करना आसान लगता है, और हद तक यह सच भी है।

लेकिन दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अक्सर कई तरह के किरदार निभाने लगते हैं। इस दौड़ में हम खुद को कई बार आलोचना और नकारात्मक भावनाओं से घेर लेते हैं, जिससे हम अपनी ही नजर में गिरने लगते हैं। आइए, हम कुछ ऐसी आदतों (Self-Love Habits) पर चर्चा करें जिनकी मदद से आप खुद से प्यार करना सीख सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं।

खुद से प्यार का मतलब क्या है?

खुद से प्यार का मतलब है अपनी कमियों और खूबियों को स्वीकार करना। इसका मतलब है खुद को महत्व देना और अपनी जरूरतों को पूरा करना। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना। इसका मतलब है खुद को खुश रखना और गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करना।

दूसरों से प्यार और खुद से प्यार में क्या है अंतर?

दूसरों की परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन जब हम दूसरों से प्यार करते हैं तो हम अक्सर उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रख देते हैं, लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपनी जरूरतों को भी पूरा करते हैं। हम अपनी खुशी को भी महत्व देते हैं।

क्यों है खुद से प्यार करना जरूरी?

बढ़ाता है कॉन्फिडेंसः जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं।

कम होगा तनावः जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम तनाव महसूस करना कम करते हैं।

मजबूत बनेंगे रिलेशन्सः जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों के साथ बेहतर रिलेशन बना पाते हैं।

खुश रहने में मिलेगी मददः जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम ज्यादा खुश रहते हैं।

कैसे करें खुद से प्यार?

अपनी कमियों को स्वीकार करेंः हर कोई परफेक्ट नहीं होता। अपनी कमियों को स्वीकार करना सीखें।

अपनी खूबियों को पहचानेंः अपनी खूबियों की एक सूची बनाएं और हर रोज उन्हें याद करें।

खुद को समय देंः हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालें और कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो।

सेहत का ख्याल रखेंः हेल्दी खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और पर्याप्त नींद लें।

अपने मन को शांत रखेंः ध्यान, योग या मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज करने से आपको शांत रहने में मदद मिल सकती है।

नकारात्मक विचारों से दूर रहेंः नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करें।

अपने आप की तारीफ करेंः हर छोटी-छोटी उपलब्धि के लिए अपनी तारीफ करें।

दूसरों की तुलना में खुद से तुलना न करेंः हर व्यक्ति अलग होता है। दूसरों से तुलना करने से बचें।

अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करेंः अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें।

माफ करना सीखेंः अपने आप को और दूसरों को माफ करना सीखें।

वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? जान लें इससे जुड़ी दिलचस्प वजह

प्यार करने वालों का फेस्टिवल यानी वैलेंटाइन डे। कपल्स के लिए ये दिन बेहद खास होता है। इसके अलावा जो लोग किसी को लव एट फर्स्ट साइड करते हैं तो भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का एक अच्छा मौका होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत कैसे और कब हुई थी।

वैलेंटाइन डे को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। खासतौर पर यंगस्टर्स में इस दिन को लेकर गजब की एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक हर दिन को त्योहार की तरह मनाते हैं, लेकिन वैलेंटाइन सेलिब्रेशन को लेकर सबसे ज्यादा तैयारियां की जाती है। इस दिन कपल्स साथ में डेट प्लान करते हैं। कोई अपने दिल की बात कहता है तो वहीं बड़े रेसंत्रा में लव थीम की कई पार्टी भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। सवाल उठता है कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने वालों में से कितने लोगों को इस दिन से जुड़ा इतिहास पता होता है। तो चलिए जान लेते हैं।

कहते हैं न कि प्यार की राह इतनी आसान नहीं होती है। इसी वजह से न जानें कितने प्रेमियों की कहानी मुकम्मल होने से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार इस कहानी में किसी ऐसे को भी कुर्बानी देनी पड़ती है जो सिर्फ उनका शुभचिंतक हो। ऐसी ही कहानी है वैलेंटाइन डे की शुरुआत होने की, जब किसी को सिर्फ इस बात की सजा मिली कि उन्होंने प्यार करने वालों को मिलवाने की सजा भुगती थी। ये कहानी तीसरी सदी की है जब संत वैलेंटाइन एक पादरी थे। इस दौरान रोम में सम्राट क्लॉडियस द्वितीय का शासन चलता था। सम्राट का मानना था कि शादी करने से पुरुषों की योद्धा बनने की ताकत पर असर पड़ता है, क्योंकि वह परिवार की जिम्मेदारियों और प्रेम से बंधे होते हैं। यही वजह थी कि क्लॉडियस द्वितीय ने शादियों पर रोक लगा दी थी। दूसरी तरफ संत वैलेंटाइन प्रेम को ईश्वर का वरदान मानते थे। इस वजह से वह प्यार करने वालों की शादी करवाते थे।

संत वैलेंटाइन और जूलिया

इस बात के बारे में जब सम्राट को पता चला तो उन्होंने इसे अपने आदेश की अवहेलना माना और उन्हें जेल में डाल दिया गया। कहा जाता है कि जेलर की बेटी का नाम जूलिया था जो देख नहा सकता था।जेलर ने संत वैलेंटाइन के पास अपनी बेटी को शिक्षा लेने के लिए भेजा। उन्होंने उसे शिक्षा दी और जूलिया की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। सम्राट ने संत वैलेंटाइन को मृत्युदंड की सजा दी थी। कहानी कहती है कि 270 ईस्वी में 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन को फांसी दी गई थी और इससे पहले उन्होंने जूलिया को एक खत लिखा था। जिसमें लिखा "फ्रॉम योर वैलेंटाइन"। इसी बलिदान की याद में पोप गेलैसियस ने 14 फरवरी के दिन को आधिकारिक रूप से वैलेंटाइन डे घोषित किया।

मलवाया था। इस आर्टिकल में जानेंगे कैसे शुरु हुआ वैलेंटाइन डे।

पुराना है इसका इतिहास?

वैलेंटाइन डे की शुरुआत 496 ईस्वी में मानी जाती है। ये 5वीं सदी थी जब पोप गेलैसियस प्रथम के द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस दिन का संबंध रोमन फेस्टिवल से भी माना जाता है। रोम की पुरानी परंपरा 'लूपरकोरिया' की जगह इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था। हालांकि 'लूपरकोरिया' फेस्टिवल 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रजनन क्षमता, शुद्धिकरण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। कहा जाता है कि इसे पैलेंटाइन हिल पर स्थित 'लूपरकल गुफा' में आयोजित करते थे। अब जान लेते हैं वैलेंटाइन की सबसे प्रचलित कहानी के बारे में।

वैलेंटाइन की कहानी

प्यार के फेस्टिवल वैलेंटाइन डे कि शुरुआत की सबसे प्रचलित कहानी है संत

बैंकों की मनमानी पर आरबीआई का चाबुक, लोन के साथ अब नहीं चिपका पाएंगे बीमा और क्रेडिट कार्ड

अगर आप भी बैंक में लोन लेने जाते हैं और बैंक अधिकारी लोन की फाइल के साथ आपको जबरदस्ती बीमा पॉलिसी या क्रेडिट कार्ड थमा देते हैं, तो यह खबर आपको बड़ी राहत देने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा की जा रही 'मिस-सेलिंग' और डिजिटल धोखाधड़ी यानी 'डार्क पैटर्न' पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय बैंक ने इसके लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो आगामी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। इन नियमों का सीधा असर यह होगा कि अब कोई भी बैंक आपकी स्पष्ट और अलग से दी गई सहमति के बिना आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं बेच पाएगा।

एक क्लिक में सहमति का खेल खत्म

अब तक डिजिटल बैंकिंग में अक्सर देखा जाता था कि ग्राहक जब लोन या किसी सेवा के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है, तो वहां पहले से टिक किए गए बॉक्स या 'आई एग्री' का एक ही बटन होता है। इस एक बटन को दबाते ही ग्राहक अनजाने में लोन के साथ-साथ बीमा और अन्य सेवाओं के लिए भी अपनी मंजूरी दे देता था। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अब यह तरीका नहीं चलेगा। नए नियमों के मुताबिक, बैंकों को हर एक प्रोडक्ट के लिए ग्राहक से अलग-अलग और स्पष्ट सहमति लेनी होगी। यानी लोन के लिए अलग हस्ताक्षर और बीमा के लिए अलग मंजूरी अनिवार्य होगी, जिससे छुपे हुए एग्रीमेंट का डर खत्म हो जाएगा।

ग्राहक की हैसियत देखकर ही बेच सकेंगे प्रोडक्ट

नए दिशा-निर्देशों में बैंकों की जवाबदेही तय की गई है कि वे ग्राहक की प्रोफाइल और जरूरत के हिसाब से ही प्रोडक्ट बेचें। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ग्राहक की आय सीमित है और बैंक उसे कोई जटिल और जोखिम भरा निवेश प्लान बेच देता है, तो इसे अब 'मिस-सेलिंग' माना जाएगा। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, वह ग्राहक की आर्थिक स्थिति से मेल खाता है या नहीं। साथ ही, यह भी स्पष्ट बताना होगा कि बेचा जा रहा प्रोडक्ट खुद बैंक का है या किसी थर्ड पार्टी कंपनी का है।

डार्क पैटर्न और एजेंटों पर भी सख्ती

आरबीआई ने डिजिटल ऐप्स और वेबसाइटों पर इस्तेमाल होने वाले 'डार्क पैटर्न' को भी प्रतिबंधित कर दिया है। अक्सर ग्राहकों को 'आज आखिरी मौका' या उल्टी गिनती वाली घड़ी दिखाकर दबाव में फैसला लेने पर मजबूर किया जाता है, जिसे अब गैर-कानूनी माना जाएगा। इसके अलावा, बैंकों में बैठे थर्ड पार्टी एजेंट अब खुद को बैंक कर्मचारी बताकर ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपनी पहचान साफ तौर पर बतानी होगी और बिक्री के लिए कॉल भी सिर्फ तय ऑफिस समय में ही करनी होगी।

नियम तोड़े तो भरना होगा हर्जाना

सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि बैंक ने गलत तरीके से या अधूरी जानकारी देकर कोई प्रोडक्ट बेचा है, तो बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा वापस करना होगा। इतना ही नहीं, अगर उस गलत प्रोडक्ट की वजह से ग्राहक को कोई आर्थिक नुकसान हुआ है, तो बैंक को उसकी भरपाई भी करनी होगी। फिलहाल आरबीआई ने इन नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है, जिस पर 4 मार्च 2026 तक सुझाव मांगे गए हैं और अंतिम रूप से 1 जुलाई 2026 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।

इंडिगो के लिए खत्म हुई राहत की अवधि, अब पायलटों के लिए लागू हुए सख्त नियम

नई दिल्ली, एजेंसी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों के पालन में मिली 68 दिनों की अस्थायी राहत मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने यह छूट दिसंबर 2025 में आए परिचालन संकट के बाद दी थी, ताकि एयरलाइन अपने पायलटों के रोस्टर और उड़ान प्रणालियों को नए सुरक्षा मानकों के अनुरूप ढाल सके। अब बुधवार, 11 फरवरी 2026 से इंडिगो को बिना किसी अतिरिक्त छूट के संशोधित नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा।

राहत की इस 68 दिनी अवधि के दौरान डीजीसीए ने इंडिगो के परिचालन पर बेहद सख्त नजर रखी। एयरलाइन को हर घंटे की फ्लाइट रिपोर्ट के साथ-साथ साप्ताहिक और पाक्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट भी जमा करनी पड़ी। इतना ही नहीं, नियामक ने हवाई अड्डों पर अपने विशेष अधिकारी तैनात किए थे और ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से इंडिगो के कामकाज की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की गई। डीजीसीए ने पहले ही साफ कर दिया था कि यह राहत केवल एक सीमित समय के लिए थी और सुरक्षा मानकों से समझौता करते हुए इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

एयरलाइन ने कहा- हम पूरी तरह तैयार

इंडिगो ने डीजीसीए को आश्वस्त किया है कि वह 11 फरवरी से नए स्नष्ठञ्जरु नियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरलाइन के अनुसार, उसने अपनी रोस्टर योजना और क्रू शेड्यूलिंग में सभी आवश्यक बदलाव कर लिए हैं। भविष्य में किसी भी तरह के व्यवधान से बचने के लिए इंडिगो ने पायलट-टू-एयरक्राफ्ट रेशियो (विमान के अनुपात में पायलटों की संख्या) को बढ़ा दिया है और एक मजबूत रिजर्व पायलट पूल तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि उनके पास अब पर्याप्त 'पायलट बफर' उपलब्ध है, जिससे सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।

दिसंबर 2025 का संकट और भारी जुर्माना

गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में इंडिगो को एक बड़े परिचालन संकट का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते 5,500 से अधिक उड़ानें रद्द हुई थीं। इस अव्यवस्था के कारण लाखों यात्रियों को परेशानी हुई, जिसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन पर 22.2 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया था। इसी संकट को संभालने और नए नियमों में बदलाव के लिए ही 68 दिनों की मोहलत दी गई थी। अब इंडिगो को पायलटों के साप्ताहिक आराम, रात की उड़ान की सीमाओं और थकान प्रबंधन से जुड़े सभी कड़े प्रावधानों को अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि नई तैयारियों के बाद अब यात्रियों को पहले जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सोना खरीदने और बेचने से पहले समझ लें टैक्स के नियम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सुरक्षित निवेश और परंपरा दोनों माना जाता है। शादी-ब्याह, त्योहारों और भविष्य की बचत के लिए लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं। लेकिन अक्सर निवेशक यह भूल जाते हैं कि सोना खरीदने, रखने और बेचने के हर चरण में टैक्स से जुड़े नियम लागू होते हैं। अगर इन नियमों की सही जानकारी न हो तो कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला सकता है। ऐसे में सोने में निवेश से पहले टैक्स की पूरी समझ होना बेहद जरूरी है।

सोना खरीदते समय सबसे पहले जीएसटी का बोझ आता है। चाहे आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदें, गोल्ड कॉइन लें या डिजिटल गोल्ड में निवेश करें, सोने की कीमत पर 3 प्रतिशत जीएसटी देना होता है। इसके अलावा, अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर लगने वाले मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत जीएसटी अलग से देना पड़ता है। यानी सोना खरीदते वक्त ही आपकी कुल लागत बढ़ जाती है।

जब आप सोना बेचते हैं, तब उस पर इनकम टैक्स (कैपिटल गेन्स टैक्स) लगता है। यह टैक्स बिक्री कीमत पर नहीं, बल्कि आपके मुनाफे पर लगाया जाता है। टैक्स की दर इस बात पर निर्भर करती है कि आपने सोना कितने समय तक अपने पास रखा। अगर आप सोना 3 साल (36 महीने) के भीतर बेचते हैं, तो इससे होने वाला मुनाफा शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (एसटीसीजी) माना जाता है और यह आपकी सालाना आय में जुड़कर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल होता है।

वहीं, अगर सोना 3 साल से ज्यादा समय बाद बेचा जाता है, तो उस पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स लगता है। इसमें 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है, लेकिन साथ ही इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता है। इंडेक्सेशन के जरिए महंगाई के अनुसार खरीद कीमत बढ़ा दी जाती है, जिससे टैक्सेबल मुनाफा कम हो जाता है। लंबे समय के निवेशकों के लिए यह ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

विरासत में मिले सोने को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, विरासत में सोना मिलने पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर आप उस सोने को बाद में बेचते हैं, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। खास बात यह है कि यहां होल्डिंग पीरियड आपकी खरीद तारीख से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की खरीद तारीख से गिना जाएगा, जिससे आपको वह सोना मिला है।

इनकम टैक्स विभाग घर में रखे जाने वाले सोने की एक सीमा भी तय करता है, बशर्ते सोने का स्रोत वैध हो। आमतौर पर बिना पूछताछ के विवाहित महिला 500 ग्राम, अविवाहित महिला 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं। इससे ज्यादा सोना रखने की स्थिति में यह साबित करना होता है कि वह विरासत में मिला है या घोषित आय से खरीदा गया है।

डिजिटल गोल्ड पर टैक्स के नियम भी लगभग फिजिकल गोल्ड जैसे ही हैं। इसे खरीदते समय 3 प्रतिशत जीएसटी लगता है और बेचते समय होल्डिंग पीरियड के आधार पर एसटीसीजी या एलटीसीजी टैक्स देना होता है।

कुल मिलाकर, सोना भले ही सुरक्षित निवेश माना जाता हो, लेकिन टैक्स नियमों को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। इसलिए सोने में निवेश से पहले टैक्स की पूरी जानकारी रखना जरूरी है, ताकि मुनाफे पर किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े।

बांग्लादेश की सत्ता में बीएनपी की वापसी, बहुमत का आंकड़ा पार, जमात का बुरा हाल

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश के आम चुनाव में सियासी तस्वीर तेजी से बदलती दिख रही है। देश में जनता ने कट्टरपंथियों की जमात को पूरी तरह नकार दिया है। भारत विरोधी रवैया रखने वाली जमात-ए-इस्लामी और उसके नेतृत्व वाला 11 दलों का गठजोड़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से पूरी तरह से हारता दिख रहा है। देश में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी करीब 20 साल के बाद सरकार बना सकती है। रॉयटर्स के अनुसार बांग्लादेश के चुनावी नतीजों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं, कट्टरपंथी दलों को अपेक्षित समर्थन नहीं मिला।

बांग्लादेशी मीडिया ढाका ट्रिब्यून के अनुसार मतगणना में बीएनपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है और अब तक 151 सीटों पर जीत दर्ज कर

चुकी है। शुरुआती रुझान बताते हैं कि जमात-ए-इस्लामी 43 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है। जबकि इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश को एक सीट और अन्य दलों को अबतक चार सीटें मिली हैं। इन रुझानों से संकेत मिल रहा है कि बीएनपी गठबंधन मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में तारिक रहमान की ताजपोशी पक्की मानी जा रही है।

बीएनपी जीती तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री?

शुरुआती अनौपचारिक नतीजों के अनुसार 299 में से 204 सीटों की गिनती पूरी होने तक बीएनपी 158 सीटों पर आगे या जीत दर्ज कर चुकी थी, जबकि जमात-ए-इस्लामी 41 और अन्य दल पांच सीटों पर रहे। बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने बोगरा सीट से 2,16,284 वोट पाकर जीत हासिल की। बीएनपी पहले ही साफ कर चुकी है कि सत्ता मिलने पर तारिक रहमान को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने ढाका-17 और बोगरा-6 सीट से जीत दर्ज की है। अगर अंतिम नतीजे इसी रुझान पर रहे तो उनका अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। बेगम खालिदा जिया 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रहीं। चुनाव प्रचार के दौरान तारिक रहमान ने अवामी लीग के समर्थकों से भी समर्थन की अपील की थी। रुझानों से संकेत मिला है कि अवामी लीग के कई पारंपरिक वोट इस बार बीएनपी की ओर गए।

मतदान के दौरान हिंसा और धमाके की घटनाएं

मतदान के दिन कई इलाकों से हिंसा और झड़प की खबरें आईं। खुलना में एक मतदान केंद्र के बाहर जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं और बीएनपी समर्थकों के बीच भिड़ंत में एक बीएनपी नेता की मौत हो गई। बीएनपी का आरोप है कि धक्का दिए जाने से वह पेड़ से टकराए और जान गई। जमात ने दावा किया कि नेता पहले से बीमार थे। गोपालगंज के निचुपाड़ा स्थित रेशमा इंटरनेशनल स्कूल मतदान केंद्र पर सुबह करीब 9 बजे हैंडबम हमला हुआ, जिसमें 13 साल की लड़की समेत तीन लोग घायल हुए। चुनाव ड्यूटी में लगे अंसार बल के दो सदस्य भी घायल हुए।

जनमत संग्रह में सुधारों को समर्थन

चुनाव के साथ अंतरिम सरकार की ओर से संवैधानिक सुधारों पर जनमत संग्रह भी कराया गया। इसमें करीब दो तिहाई मतदाताओं ने सुधारों के पक्ष में राय दी। यह जनमत संग्रह चुनावी प्रक्रिया के साथ ही आयोजित हुआ। इसे अंतरिम प्रशासन के एजेंडे का अहम हिस्सा बताया गया। अधिकारियों के अनुसार सुधारों का मकसद शासन व्यवस्था में बदलाव और संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है।

बांग्लादेश की राजनीति का नया चेहरा : मां पूर्व पीएम तो पिता पूर्व राष्ट्रपति, तारिक रहमान के परिवार में कौन-कौन?

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश के 2026 के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की ऐतिहासिक जीत में तारिक रहमान की रणनीतिक और करिश्माई भूमिका ने केंद्रबिंदु की तरह काम किया। लंबे निर्वासन और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने पार्टी को एकजुट किया, युवा मतदाताओं को आकर्षित किया और जनसमर्थन की नई लहर खड़ी की। यह जीत सिर्फ बीएनपी की नहीं, बल्कि तारिक रहमान की नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक दृष्टि का प्रतीक बनकर उभरी है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि बांग्लादेश की राजनीति दशकों से दो मुख्य पारिवारिक-राजनीतिक धारणाओं के बीच घूमती रही है। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत खालिदा जिया की विरासत के बीच। ऐसे में 2026 के चुनावों में बीएनपी की जीत और तारिक रहमान की उभरती भूमिका यह संकेत देती है कि अब देश का नेतृत्व एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर सकता है। 20 नवंबर 1965 को जन्मे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के वरिष्ठ नेता और पार्टी के चेयरमैन हैं। वह पार्टी की सर्वोच्च राजनीतिक इकाई का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू किया। वे बांग्लादेश के इतिहास में एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता जिया उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिनकी 1981 में हत्या हो गई थी। उनकी मां बेगम खालिदा जिया 1991 से 1996 व 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं और बीएनपी की प्रमुख चेयरपर्सन थीं। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों से ही तारिक अपने परिवार की राजनीति में शामिल रहे हैं और बीएनपी के भीतर स्थायी भूमिका निभाई है। तारिक रहमान की मां और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने 3 जनवरी 1982 को पहली बार बीएनपी के सदस्य के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। बाद में वे बीएनसपी की अध्यक्ष बनीं और अपनी मौत तक वह इस पद पर रहीं।

जिया 1991 में पहली बार बनीं पीएम

खालिदा जिया साल 1991 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं। इसके साथ ही बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी हासिल किया। इसके बाद साल 2001 से 2006 तक दूसरी बार भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनीं। बताते चले कि खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1946 को अविभाजित भारत के दिनाजपुर जिले में हुआ। उनकी माता का नाम तैयबा और पिता का नाम इसकंदर मजूमदार था। खालिदा का परिवार जलपाईगुड़ी में चाय का व्यापार करता था और वहां से पलायन करके दिनाजपुर पहुंचा था। साल 1960 में खालिदा जिया की शादी आर्मी कैप्टन जिया उर रहमान के साथ हुई, जो बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। साल 1983 में जब खालिदा बीएनपी चीफ बनीं तो उनकी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने खालिदा की काबिलियत पर शक जताते हुए पार्टी छोड़ दी।

तारिक रहमान के पिता और पूर्व बांग्लादेशी राष्ट्रपति

अब तारिक रहमान के पिता के बारे में जानते हैं। तारिक रहमान के पिता जिया उर रहमान ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी और देश के सैनिक-राजनीतिक नेता थे। वे 1975 में सैनिक हस्तक्षेप के बाद सत्ता में आए और 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने बीएनपी की स्थापना की और लोकतांत्रिक बहुदलीय राजनीति को मजबूती दी। 1981 में उनकी हत्या हुई, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत आज भी बीएनपी और देश की राजनीति में जीवित है।

नीदरलैंड की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी हुई हैक : 60 लाख ग्राहकों के बैंक-पासपोर्ट का डाटा चोरी, मामले की जांच शुरू

एम्सटर्डैम, एजेंसी। नीदरलैंड की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी ओडिडो पर साइबर हमलावरों ने बड़ा हमला बोल दिया है। कंपनी ने खुद माना कि हैकर्स ने उसके सिस्टम में घुसकर 60 लाख से ज्यादा ग्राहकों का निजी डेटा चुरा लिया। यह डेटा बहुत संवेदनशील है। इसमें लोगों के बैंक खाते की जानकारी और पासपोर्ट नंबर जैसी चीजें शामिल हैं। यह नीदरलैंड में अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक मामला बन गया है। कंपनी ने ग्राहकों को चेतावनी भेजी है और जांच शुरू कर दी है।

ओडिडो ने सात फरवरी को संदेह होने पर जांच शुरू की। कंपनी ने अपने अंदरूनी विशेषज्ञों और बाहर के एक्सपर्ट्स की मदद ली। जांच में पता चला कि हैकर्स ने कंपनी के उस सिस्टम पर हमला किया जिससे ग्राहकों से संपर्क किया जाता है। कंपनी ने तुरंत अनधिकृत पहुंच रोक दी। अब कंपनी का कहना है कि फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करना पूरी तरह सुरक्षित है। प्रभावित ग्राहकों को

ईमेल भेजकर सूचित किया गया है कि उनका डेटा प्रभावित हो सकता है।

कंपनी की कार्रवाई

ओडिडो ने इस घटना की सूचना नीदरलैंड की प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन संस्था एपी को दे दी है। कंपनी ने कहा है कि वह पूरी जांच कर रही है और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रही है। कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और कोई संदिग्ध ईमेल या मैसेज पर ध्यान न दें। ओडिडो ने यह भी बताया कि हमले के बाद सिस्टम को सुरक्षित कर लिया गया है।

कंपनी के बारे में

ओडिडो पहले टी-मोबाइल का डच बिजनेस था। 2021 में इसे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स अपैक्स और वॉरबर्ग पिंकस ने खरीद लिया था। कंपनी नीदरलैंड में करीब 80 लाख ग्राहकों को सेवा देती है। वहां के बाजार में यह केपीएन और वोडाफोनजिग्गो जैसी बड़ी कंपनियों से मुकाबला करती है। यह हमला कंपनी की छवि पर बड़ा असर डाल सकता है।

ग्राहकों के लिए सलाह

यह हमला दिखाता है कि साइबर खतरा कितना बड़ा है। ग्राहकों को अपने बैंक खातों पर नजर रखनी चाहिए। पासवर्ड बदलने चाहिए और दो-कारक प्रमाणीकरण चालू करना चाहिए। कंपनी ने कहा है कि वह प्रभावित लोगों की मदद के लिए कदम उठा रही है। नीदरलैंड की सरकार और प्राइवेसी वॉचडॉग इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं। ऐसे हमलों से बचने के लिए हर कोई सतर्क रहना जरूरी है।

ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी, कहा- डील नहीं तो भुगतने होंगे दर्दनाक नतीजे, अप्रैल में करेंगे चीन का दौरा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक साथ दो बड़े अंतरराष्ट्रीय संकेत दिए हैं। एक तरफ उन्होंने ईरान को परमाणु समझौते पर चेतावनी दी है, तो दूसरी ओर चीन के साथ रिश्तों को मजबूत बताया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता जरूरी है, वरना हालात बहुत खराब हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस्राइल के प्रधानमंत्री के साथ अपनी हालिया बैठक को सकारात्मक बताया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली मुलाकात की भी जानकारी दी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ समझौता करना चाहता है, ताकि टकराव की स्थिति न बने। उन्होंने साफ कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हालात बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वह तनाव नहीं चाहते, लेकिन बिना समझौते के स्थिति अलग दिशा में जा सकती है। उनका बयान ऐसे समय आया है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बना हुआ है।

नेतन्याहू संग बैठक का जिक्र

ट्रंप ने बताया कि उनकी इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हाल ही में अच्छी बैठक हुई। उन्होंने इसे बहुत उपयोगी बातचीत बताया। माना जा रहा है कि इस बैठक में ईरान, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। ट्रंप के बयान से संकेत मिला कि इस्राइल और अमेरिका इस मुद्दे पर करीबी तालमेल में हैं।

चीन दौरे का ऐलान

राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वह अप्रैल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने जाएंगे। उन्होंने बताया कि शी जिनपिंग भी इस साल बाद में अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने कहा कि इस समय अमेरिका और चीन के संबंध अच्छे हैं और वह इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, तकनीक और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार बातचीत चल रही है।

सेवा प्रदाताओं का डायरिया रोकथाम पर अभिमुखीकरण

दरभंगा। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में पापुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया (पीएसआई इंडिया) और केनव्यू के सहयोग से जिले में चल रहे "डायरिया से डर नहीं" कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को सेवा प्रदाताओं की अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गयी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के शिशु रोग विभाग के सेमिनार हॉल में आयोजित इस कार्यशाला में छह चिकित्सा पदाधिकारी एवं 30 स्टाफ नर्सेज ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदाताओं के माध्यम से डायरिया के बारे में समुदाय को विस्तार से जानकारी देना, ओआरएस और जिंक से डायरिया रोकथाम के उपायों के बारे में बताना था।

कार्यशाला में पीएसआई इंडिया के संजय तरुण ने 'डायरिया से डर नहीं' कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 13 और बिहार के तीन जिलों में चलाया जा रहा है, जिसमें शून्य से पांच साल तक के बच्चों की डायरिया के कारण होने वाली मृत्यु दर को शून्य करना और दस्त प्रबंधन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि डायरिया से किसी भी बच्चे की मौत न होने पाए, इसमें सेवा प्रदाता बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

इस मौके पर शिशु रोग विभाग के प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि समुदाय स्तर पर यह संदेश पहुंचाना जरूरी है कि टीकाकरण सारणी के अनुसार बच्चे को सारे टीके लगवाएं और रोटावायरस, विटामिन ए को लेना न भूलें। भोजन को ढककर रखें ताकि मक्खियाँ उस पर न बैठें। जिंक की खुराक को दस्त ठीक होने के बाद भी 14 दिनों तक जारी रखें। पीने के पानी को साफ़ रखें और पीने के पानी को निकालने के लिए डंडीदार लोटे का प्रयोग करें । छह माह से छोटे बच्चों को दस्त होने पर भी स्तनपान जारी रखें। डायरिया के दौरान ओआरएस से शरीर में पानी की कमी को रोकें। इन संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने में सेवा प्रदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। डॉ. अशोक कुमार ने कहा कि समुदाय में डायरिया को लेकर आज भी कई तरह की भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिनको दूर करना भी बहुत जरूरी है। लोगों में भ्रांति है कि सर्दियों में बच्चे को दस्त होने पर ओआरएस नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे को ठंड लग सकती है जबकि ऐसा कदापि नहीं है ओआरएस दस्त से बच्चे के शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और जान बचाता है। स्टाफ नर्स नूतन कुमारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों में यह भी भ्रम है कि दस्त होने पर बच्चे को ठोस आहार नहीं देना चाहिए, ऐसा कतई नहीं है ,छह महीने से बड़े बच्चों को हल्का और पचने वाला आहार देना जारी रखें। दस्त का सही समय पर उपचार बेहद जरूरी है क्योंकि उपचार न मिलना बच्चे के जीवन को संकट में डाल सकता है।

ट्रंप के न्योते पर 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होगा भारत? विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

नई दिल्ली, एजेंसी। गाजा के लिए नवगठित शांति बोर्ड में शामिल होने के अमेरिकी निमंत्रण पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है। गुरुवार (12 फरवरी) को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान इससे जुड़े एक सवाल पर भारत के रुख को लेकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'शांति बोर्ड' में शामिल होने का न्योता मिला है। फिलहाल हम प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'शांति बोर्ड के संबंध में, हमें अमेरिकी सरकार से 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हम वर्तमान में इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं।'

शांति बोर्ड पर विदेश मंत्रालय का बयान

जायसवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमें अमेरिका की ओर से शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हम फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं भारत ने पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और संवाद को बढ़ावा देने के प्रयासों का लगातार समर्थन किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस पहल का स्वागत किया है, जो गाजा सहित इस क्षेत्र में दीर्घकालिक और स्थायी शांति की दिशा में मार्ग प्रशस्त करती है।' बता दें कि गाजा के पुनर्निर्माण पर चर्चा करने के लिए 19 फरवरी को वाशिंगटन में बोर्ड की पहली बैठक आयोजित होगी।

ट्रंप ने की शांति बोर्ड की स्थापना

बता दें कि पिछले महीने (22 जनवरी) अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति बोर्ड का शुभारंभ किया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान 'बोर्ड ऑफ पीस' के चार्टर पर पाकिस्तान सहित 14 देशों ने द स्त ख त किए थे। जि स का उ द्दे श्य गा जा पट्टी में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और अस्थायी शासन की निगरानी करना है। हालांकि फिर इसका विस्तार करते हुए कहा गया कि इसे सिर्फ गाजा तक ना सीमित न रहकर वैश्विक संघर्षों से निपटने में मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, जिसकी अध्यक्षता वे खुद करेंगे।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका ने लगभग 60 देशों को बोर्ड में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। जिस पर अजरबैजान, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, इंडोनेशिया, इस्राइल, जॉर्डन, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, तुर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान और वियतनाम सहित लगभग 27 देशों ने इस पहल में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन सहित कई पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों ने इसमें भाग न लेने का विकल्प चुना है।

उम्र का फासला दरकिनार कर जब हमसफर बने ये सेलेब्स, लिस्ट में करीना-सैफ से निक-प्रियंका तक शामिल

वैलेंटाइन डे के मौके पर उन बॉलीवुड सेलिब्रिटी जोड़ियों की बात की करते है। जिनके बीच उम्र का अच्छा-खासा फासला है लेकिन उनका रिश्ता में आज भी उतना ही प्यारा और मजबूती है।

कहते हैं प्यार में उम्र नहीं देखी जाती लेकिन जब कोई मशहूर चेहरा अपने से काफी छोटे या बड़े पार्टनर के साथ शादी करता है तो चर्चा होना तय है। सोशल मीडिया से लेकर गॉसिप कॉलम तक हर जगह सवाल उठते हैं। लेकिन कई सेलिब्रिटी कपल्स ने समय के साथ ये साबित कर दिया कि असली मायने समझ भरोसे और साथ निभाने के होते हैं।

कहते हैं प्यार में उम्र मायने नहीं रखती लेकिन जब बात सेलिब्रिटीज की आती है तो लोगों की नजर सबसे पहले उम्र के फासले पर ही जाती है। बड़ी एज गैप वाली जोड़ियों पर अक्सर सवाल उठते हैं। बातें बनती हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन कई स्टार कपल्स ने ये साबित किया है कि रिश्ता भरोसे, समझ और साथ से चलता है ना कि उम्र से। वैलेंटाइन डे के मौके पर जानते हैं उन मशहूर जोड़ियों के बारे में जिनके बीच अच्छा-खासा उम्र का अंतर है फिर भी उनका प्यार पहले जैसा ही मजबूत है।

प्रियंका और निक

प्रियंका और निक की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 2016 में निक ने प्रियंका को मैसेज किया था और 2017 में दोनों पहली बार वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी में मिले थे। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और 2018 में जोधपुर में तीन दिन तक चली शाही शादी में हिंदू और क्रिश्चियन दोनों रीति-रिवाजों से शादी की थी। उस वक्त प्रियंका 36 साल की थीं और निक 25 के थे। दोनों के उम्र में करीब 11 साल का अंतर था। उम्र के फासले को लेकर खूब बातें भी हुईं लेकिन प्रियंका ने साफ कहा कि अब उन्हें ऐसी अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता है।

शाहिद और मीरा

सैफ और करीना

सैफ और करीना की मोहब्बत फिल्म 'टशन' के सेट पर शुरू हुई थी। 2012 में करीना ने पटौदी के नवाब सैफ अली खान से शादी की थी। दोनों के बीच 10 साल का अंतर है लेकिन उनकी बॉन्डिंग और दोस्ती हर इवेंट में साफ नजर आती है। आज ये दोनों तैमूर और जेह के पेरेंट्स हैं और अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।

शाहिद और मीरा की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। साल 2014 में दोनों परिवारों ने मिलवाया और पहली ही मुलाकात करीब 7 घंटे चली थी। 14 साल का एज गैप होने के बावजूद दोनों की समझ इतनी अच्छी रही कि 2015 में सादगी भरे समारोह में दोनों ने शादी कर ली थी। आज ये जोड़ी दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही है और अक्सर कपल गोल्स देती नजर आती है।

रणबीर और आलिया

रणबीर और आलिया का रिश्ता 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग के दौरान करीब आया था। लॉकडाउन में दोनों साथ रहने लगे और 2022 में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शादी की थी।

आपको बता दें दोनों की उम्र में 11 साल का अंतर है। रणबीर आलिया से 11 साल बड़े है।

जेनेलिया और रितेश की कहानी

दोस्ती से शुरू हुई थी। 2003 में फिल्म 'तुझे मेरी कसम' के सेट पर मुलाकात हुई फिर दोस्ती प्यार में बदली और 2012 में शादी कर ली। दोनों की उम्र में 9 साल का अंतर है। दोनों आज दो बच्चों के माता-पिता हैं और अपनी मस्तीभरी केमिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com